NYCS
RNI: DELBIL/2008/25219, ₹20

युवा सहकार

www.nycsindia.com
सितंबर 2026, नई दिल्ली

अर्बन कोऑपरेटिव बैंक बनेंगे मॉडर्न

अंदर के पन्नों पर
एआई की नैतिकता पर अंतरराष्ट्रीय युवा सहकारी नेताओं ने की चर्चा
पैक्स में लागू होगी नई एचआर पॉलिसी

National Yuva Co-operative Society Limited

NYCS

Empowering Financial Independence

Our Services

Loans: Small, medium, and large loans at highly competitive interest rates, catering to the diverse financial needs of our members.

Deposits: Attractive interest rates, with special benefits for senior citizens and women.

Simplified Process: Our streamlined application process and flexible terms ensure that financial assistance is always within reach.

Our Reach

- Presence in All States & Union Territories
- 37 Branches Nationwide
- 600+ Districts Served by Our Representatives
- Central Administration Office (CAO) in Pune, Led by Senior Banking & Finance Professionals

Why Choose NYCS Ltd.?

- **Trusted Expertise –** Over 20 years in financial services.
- **Nationwide Presence –** A rapidly growing network.
- **Member-Focused –** Tailored financial solutions.
- **Youth Empowerment –** Supporting young entrepreneurs.

Contact Us

209, 2nd Floor, A2B, Vardhman Janak Market, Janakpuri, New Delhi-58
+91 9205595944
011-45096652/40153681
nycs.ltd@gmail.com
www.nycsindia.com

Together, let's build a brighter financial future!

युवा सहकार

वर्ष : 03, अंक-03, सितंबर-2026

निदेशक मंडल
एनवाईसीएस

प्रकाश चंद्र साहू
मनीष कुमार
राजेश बाबूलाल पांडे
प्रकृति क्षितिज पंड्या
ज्योतिर्मय सिंह महतो
गौरव पांडेय
हिरेन मधुसूदन शाह
राघव गर्ग
आशुतोष सतीश गुप्ता
दर्शन सोलंकी (विशेष आमंत्रित)
देवेन्द्र सिंह (विशेष आमंत्रित)
रामचंद्र दत्तात्रेय कुलकर्णी (सीईओ)

कार्यालय

नेशनल युवा कोऑपरेटिव सोसायटी लिमिटेड (एनवाईसीएस)
209, द्वितीय तल, ए2बी, वर्द्धमान जनक मार्केट, जनकपुरी, नई दिल्ली - 110058
मोबाइल नंबर : 9205595944
लैंडलाइन नंबर : 011-45096652/40153681
E-mail: nycs.ltd@gmail.com
Web: www.nycsindia.com

Registration No
DELBIL/2008/25219

संकल्पना, कंटेंट व डिजाइन : फार्च्यूना कम्यूनिकेशंस प्रा. लि., नई दिल्ली

नेशनल युवा कोऑपरेटिव सोसायटी लिमिटेड, नई दिल्ली द्वारा प्रकाशित एवं फर्स्ट इंप्रेशन कॉरपोरेट सर्विस प्रा. लि., सेक्टर-63, नोएडा, गौतमबुद्ध नगर, यूपी द्वारा मुद्रित।

कार्यकारी संपादक: अभिषेक कुमार
पीआरबी एक्ट के तहत खबरों के चयन के उत्तरदायी।

NYCSIndia

शहरी सहकारी बैंकों की बदलेगी सूरत 04

छोटे शहरों के युवाओं को एआई और क्लाउड का प्रशिक्षण 05

06 अर्बन कोऑपरेटिव बैंक बनेंगे मॉडर्न

18 एआई की नैतिकता पर अंतरराष्ट्रीय युवा सहकारी नेताओं ने की चर्चा

पैक्स में लागू होगी नई एचआर पॉलिसी 20

पैक्स बनेंगे वन स्टॉप शॉप 24

एग्रीकल्चर छात्रों को अब सीधे खाते में मिलेगी स्कॉलरशिप 26

डिजिटल सहकारिता: गांव की चौपाल से डिजिटल प्लेटफॉर्म तक 27

टीएसयू में शुरू हुए नए कोर्स 30

एशियाड में स्वर्ण जीत ओलंपिक के लिए क्वॉलिफाई करना अगला लक्ष्य: सविता 32

शहरी सहकारी बैंकों की बदलेगी सूरत

को-ऑपरेटिव बैंकों में घपलों-घोटालों का लंबा इतिहास रहा है। इसके पीछे सख्त कानून और नियमों का न होना, नियामकीय निगरानी और अपारदर्शिता का अभाव और कोऑपरेटिव्स के सदस्यों और लीडर्स द्वारा मनमाने फैसले लेने जैसी वजहें रही हैं। सहकारिता मंत्रालय के गठन के बाद से कानून में संशोधन और कोऑपरेटिव बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक के दायरे में लाने से इन बैंकों की कार्यशैली में लगातार सुधार हो रहा है। खासकर शहरी सहकारी बैंकों को आधुनिक बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। इसका मकसद शहरी सहकारी बैंको को निजी और सार्वजनिक बैंकों से प्रतिस्पर्द्धा करने लायक बनाना है ताकि ये बैंक भी अपने ग्राहकों को उनके जैसी सुविधाएं उपलब्ध करा सकें।

आज बैंकिंग सुविधाएं बैंक शाखाओं से निकल कर मोबाइल के माध्यम से हर हाथ तक पहुंच गई है, ऐसे में शहरी सहकारी बैंकों को आधुनिक एवं पारदर्शी बनाना और भी जरूरी हो गया है। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह का जोर शहरी सहकारी बैंकों में व्यापक परिवर्तन लाने पर है। इसके लिए ही शहरी सहकारी बैंकों के अंब्रेला ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर नेशनल अर्बन कोऑपरेटिव फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (एनयूसीएफडीसी) का गठन किया गया है।

आज बैंकिंग सुविधाएं बैंक शाखाओं से निकल कर मोबाइल के माध्यम से हर हाथ तक पहुंच गई है, ऐसे में शहरी सहकारी बैंकों को आधुनिक एवं पारदर्शी बनाना और भी जरूरी हो गया है। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह का जोर शहरी सहकारी बैंकों में व्यापक परिवर्तन लाने पर है। इसके लिए ही शहरी सहकारी बैंकों के अंब्रेला ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर नेशनल अर्बन कोऑपरेटिव फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (एनयूसीएफडीसी) का गठन किया गया है। देश के लगभग 1,400 शहरी सहकारी बैंकों को एक अंब्रेला ऑर्गेनाइजेशन से जोड़ने का उद्देश्य टेक्नोलॉजी, ट्रेनिंग, कम्प्लायंस और आधुनिक बैंकिंग सुविधाओं तक उनकी पहुंच बढ़ाना है। इसका काम शहरी सहकारी बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित अनुपालन मानकों को पूरा करने में आवश्यक मार्गदर्शन देना और बैंकों के सुचारू संचालन के लिए तकनीकी एवं संस्थागत सहयोग उपलब्ध कराना है। बैंकिंग क्षेत्र में हो रहे नए सुधारों और नियामकीय बदलावों की जानकारी भी यह शहरी सहकारी बैंकों को उपलब्ध कराएगा। इससे शहरी सहकारी बैंक आधुनिक बैंकिंग प्रतिस्पर्धा में अन्य बैंकों के साथ समान स्तर पर खड़े हो सकेंगे।

शहरी सहकारी बैंकों को नया जीवन देने, उनकी पहुंच का विस्तार करने और उन्हें विश्वसनीय बनाने के लिए 'बैंक इन बॉक्स' सेवा का भी शुभारंभ किया गया है। इसके माध्यम से शहरी सहकारी बैंकों को कोर बैंकिंग, डिजिटल भुगतान, क्लाउड सेवाएं, नियामकीय अनुपालन तथा आधुनिक बैंकिंग से जुड़ी अनेक सुविधाएं एक ही एकीकृत प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होंगी। यह पहल छोटे बैंकों को तकनीकी रूप से सक्षम बनाने और उन्हें प्रतिस्पर्धी बैंकिंग व्यवस्था से जोड़ने का रास्ता तैयार करेगी।

इन बैंकों को साइबर सुरक्षा और डिजिटल फोरेंसिक सुविधा उपलब्ध कराने के लिए एनयूसीएफडीसी का राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय (एनएफएसयू) से एमओयू हुआ है। इस साझेदारी से शहरी सहकारी बैंकों तथा उनके ग्राहकों की डिजिटल सुरक्षा मजबूत होगी। साथ ही छोटे से छोटे शहरी सहकारी बैंक की प्रत्येक शाखा तक साइबर सुरक्षा और डिजिटल फोरेंसिक से जुड़ी सुविधाएं अत्यंत कम लागत पर मिलेगी।

शहरी सहकारी बैंकों का ग्राहक आधार छोटे दुकानदार, व्यापारी, कुटीर उद्योग, एमएसएमई, स्थानीय उद्यमी, महिला स्वयं सहायता समूह और मध्यम वर्ग के लोग हैं। ये अपने ग्राहकों को आधुनिक सुविधाएं और बेहतर वित्तीय सहायता उपलब्ध कराकर सहकारी व्यवस्था को सशक्त बनाने में और महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। आधुनिक बैंकिंग के लिए डिजिटल बैंकिंग, रियल-टाइम भुगतान, साइबर और डेटा सुरक्षा, एआई (कृत्रिम बुद्धिमत्ता) आधारित धोखाधड़ी रोकथाम प्रणाली तथा नियामकीय मानकों की पूर्ति में अंब्रेला ऑर्गेनाइजेशन शहरी सहकारी बैंकों की सहायता करेगा।■

प्रकाश चंद्र साहू
अध्यक्ष, नेशनल युवा कोऑपरेटिव सोसायटी लिमिटेड

छोटे शहरों के युवाओं को एआई और क्लाउड का प्रशिक्षण

युवा सहकार टीम

देश के युवाओं को भविष्य की तकनीकी नौकरियों के लिए तैयार करने की दिशा में राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी) ने बड़ी पहल की है। कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के मार्गदर्शन में एनएसडीसी ने कल्ट्स एजुकेशन और अमेजॉन वेब सर्विसेज के सहयोग से देशव्यापी क्लाउड और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कौशल कार्यक्रम शुरू किया है। इसका खास फोकस टियर-2 और टियर-3 शहरों के उन युवाओं पर है, जिन्हें बड़े शहरों की तुलना में आधुनिक तकनीकी प्रशिक्षण के कम अवसर मिलते हैं।

इस कार्यक्रम के माध्यम से 1.50 लाख शिक्षार्थियों को एआई और क्लाउड कंप्यूटिंग की बुनियादी जानकारी दी जाएगी। इनमें से 10 हजार युवाओं को गहन प्रशिक्षण देकर रोजगार के लिए तैयार किया जाएगा। यह पहल देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों तक पहुंचेगी और कम सुविधा वाले समुदायों के युवाओं को भी प्राथमिकता दी जाएगी।

1.50 लाख युवाओं को बुनियादी प्रशिक्षण, 10 हजार को नौकरी के लिए तैयार करेगा विशेष कार्यक्रम

छोटे शहरों तक पहुंचेगा भविष्य का कौशल

एआई और क्लाउड कंप्यूटिंग तेजी से बदलती डिजिटल दुनिया के महत्वपूर्ण कौशल बन चुके हैं। कंपनियों में डेटा, ऑनलाइन सेवाओं, साइबर सुरक्षा और डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग बढ़ने के साथ इन क्षेत्रों में प्रशिक्षित युवाओं की जरूरत भी बढ़ रही है। लेकिन छोटे शहरों के युवाओं के सामने अच्छी ट्रेनिंग, उद्योग से जुड़ाव और मान्यता प्राप्त प्रमाणपत्र हासिल करना बड़ी चुनौती रहती है। एनएसडीसी की यह पहल इसी अंतर को कम करने की कोशिश है। सबसे बड़ी सुविधा यह है कि कार्यक्रम 100 प्रतिशत ऑनलाइन होगा। युवाओं को प्रशिक्षण के लिए दिल्ली, बेंगलुरु, हैदराबाद, मुंबई या किसी अन्य महानगर में जाने की जरूरत नहीं होगी। वे अपने शहर या घर से ही आधुनिक तकनीक सीख सकेंगे।

एनएसडीसी बनेगा युवाओं और उद्योग के बीच सेतु

इस कार्यक्रम में एनएसडीसी की भूमिका केवल प्रशिक्षण उपलब्ध कराने तक सीमित नहीं है। इसका उद्देश्य युवाओं को ऐसे कौशल देना है, जिनकी उद्योग में वास्तविक मांग है, और फिर उन्हें रोजगार के अवसरों से जोड़ना है। एनएसडीसी द्वारा चुने गए डिलीवरी पार्टनर कल्ट्स एजुकेशन के माध्यम से कार्यक्रम को लागू किया जाएगा। वहीं एडब्ल्यूएस अपनी डिजिटल प्रशिक्षण सामग्री और एडब्ल्यूएस रीस्टार्ट कार्यक्रम के जरिए तकनीकी प्रशिक्षण उपलब्ध कराएगा। शुरुआती स्तर पर 1.50 लाख युवा अपनी गति से एआई और क्लाउड की बुनियादी जानकारी हासिल कर सकेंगे। जो प्रतिभागी आगे के प्रशिक्षण के लिए तैयार होंगे उन्हें एडब्ल्यूएस रीस्टार्ट में शामिल होने का अवसर मिलेगा।

10 हजार को जॉब-रेडी ट्रेनिंग

एडब्ल्यूएस रीस्टार्ट के माध्यम से 10 हजार प्रतिभागियों को क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर, नेटवर्किंग, साइबर सुरक्षा, प्रोग्रामिंग, रिलेशनल डेटाबेस और एआई के मूल सिद्धांत सिखाए जाएंगे। यह प्रशिक्षण केवल किताबों और ऑनलाइन लेक्चर तक सीमित नहीं रहेगा। युवाओं को प्रैक्टिकल लैब, वास्तविक परिस्थितियों पर आधारित अभ्यास और अनुभवी प्रशिक्षकों तथा मेंटर्स का मार्गदर्शन भी मिलेगा। प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा करने वालों को एडब्लूएस का उद्योग में मान्यता प्राप्त प्रमाणपत्र मिलेगा। इसके साथ योग्य प्रतिभागियों को स्थानीय नियोक्ताओं के साथ योग्यता आधारित साक्षात्कार के अवसर भी मिलेंगे।

विकसित भारत से जुड़ा लक्ष्य

केंद्रीय कौशल विकास राज्य मंत्री जयंत चौधरी ने इस पहल को विकसित भारत 2047 के लक्ष्य से जोड़ते हुए कहा है कि भविष्य का भारत तभी मजबूत होगा, जब अवसर किसी युवा के शहर या सामाजिक पृष्ठभूमि से तय न हों। कार्यक्रम के अंत में राष्ट्रीय हैकाथॉन भी आयोजित किया गया। ■

अर्बन कोऑपरेटिव बैंक बनेंगे मॉडर्न

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने मुंबई में एनयूसीएफडीसी के नए परिसर का किया उद्घाटन

'सहकार नव-क्रांति' कार्यक्रम में बोले अमित शाह- शहरी सहकारी बैंकों को आधुनिक व पारदर्शी बना रहा एनयूसीएफडीसी

एनयूसीएफडीसी से बैंकों को टेक्निकल सपोर्ट, आरबीआई गाइडलाइंस के अनुरूप व्यवस्था, कर्मचारियों की ट्रेनिंग और म्यूल हंटर जैसे जरूरी सॉफ्टवेयर मिलेंगे

युवा सहकार टीम

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के 'सहकार से समृद्धि' के विजन को आगे बढ़ाते हुए केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह शहरी सहकारी बैंकों को आधुनिक बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। उनका मकसद शहरी सहकारी बैंको को आधुनिक, पारदर्शी और सुरक्षित बनाना है ताकि ये बैंक निजी और सार्वजनिक बैंकों से प्रतिस्पर्द्धा कर सकें और अपने ग्राहकों को उनके जैसी सुविधाएं उपलब्ध करा सकें। आज जब डिजिटल क्रांति के दौर में बैंकिंग सुविधाएं बैंक शाखाओं से निकल कर हर हाथ में पहुंच गई है, ऐसे में शहरी सहकारी बैंकों की यह न सिर्फ जरूरत है, बल्कि समय की मांग भी है। इसी सोच को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री शहरी सहकारी बैंकों में आमूलचूल परिवर्तन पर जो दे रहे हैं।

इसी सिलसिले में मुंबई के बीएसई इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में 'सहकार

एनयूसीएफडीसी का उद्देश्य मुनाफा कमाना नहीं, बल्कि अर्बन कोऑपरेटिव बैंकों को आधुनिक बनाकर उन्हें देश और दुनिया की स्पर्धा में खड़ा करना है

देश के लगभग 1,400 शहरी सहकारी बैंकों को एक साझा अंब्रेला ऑर्गेनाइजेशन से जोड़ने का उद्देश्य टेक्नोलॉजी, ट्रेनिंग, कम्प्लायंस और आधुनिक बैंकिंग सुविधाओं तक उनकी पहुंच बढ़ाना है

'बैंक इन ए बॉक्स' से हर शाखा को कोर बैंकिंग, डिजिटल भुगतान और क्लाउड कम्प्लायंस किफायती दरों पर एक ही बॉक्स में मिलेंगे

एनयूसीएफडीसी और एनएफएसयू के बीच हुए एमओयू से छोटे से छोटे शहरी सहकारी बैंकों की ऑनलाइन बैंकिंग को भी फॉरेंसिक साइंस की सुरक्षा मिल सकेगी

नव-क्रांति' कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान अमित शाह ने शहरी सहकारी बैंकों के लिए सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर और राष्ट्रव्यापी सेवा बंडल के अंतर्गत कोर बैंकिंग तथा उससे जुड़ी सेवाओं का शुभारंभ किया। इस अवसर पर नेशनल अर्बन कोऑपरेटिव फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (एनयूसीएफडीसी) और राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय (एनएफएसयू) के बीच एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) हुआ। एनयूसीएफडीसी शहरी सहकारी बैंकों का अंब्रेला संगठन है। इससे पहले केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने मुंबई के फोर्ट स्थित शारदा सदन में एनयूसीएफडीसी के नए कार्यालय परिसर का उद्घाटन भी किया।

'सहकार नव-क्रांति' कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा, 'वर्षों से प्रतीक्षित शहरी सहकारी बैंकों का अंब्रेला ऑर्गेनाइजेशन अब भारतीय रिजर्व बैंक की मान्यता, पर्याप्त पूंजी और अपने नए कार्यालय के साथ जमीनी हकीकत बन गया है। अंब्रेला ऑर्गेनाइजेशन शहरी सहकारी बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित अनुपालन मानकों को पूरा करने में आवश्यक मार्गदर्शन देगा और बैंकों के सुचारू संचालन के लिए तकनीकी तथा संस्थागत सहयोग उपलब्ध कराएगा। इसके माध्यम से बैंकिंग क्षेत्र में हो रहे नए सुधारों और नियामकीय बदलावों की जानकारी शहरी सहकारी बैंकों तक समय पर पहुंच सकेगी। म्यूल हंटर जैसे आवश्यक सॉफ्टवेयर, आधुनिक तकनीकी समाधान और कर्मचारियों के प्रशिक्षण की सुविधा इस संगठन के माध्यम से उपलब्ध होगी, जिसकी इस क्षेत्र को अत्यंत आवश्यकता है।'

सहकारी बैंकिंग सुविधाओं का होगा विस्तार

यह अंब्रेला संगठन पारदर्शिता बढ़ाकर ग्राहकों और भारतीय रिजर्व बैंक दोनों का विश्वास मजबूत करने का मार्ग भी प्रशस्त

अंब्रेला ऑर्गेनाइजेशन शहरी सहकारी बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित अनुपालन मानकों को पूरा करने में आवश्यक मार्गदर्शन देगा और बैंकों के सुचारू संचालन के लिए तकनीकी तथा संस्थागत सहयोग उपलब्ध कराएगा। इसके माध्यम से बैंकिंग क्षेत्र में हो रहे नए सुधारों और नियामकीय बदलावों की जानकारी शहरी सहकारी बैंकों तक समय पर पहुंच सकेगी।

> **एनएफएसयू ने साइबर सुरक्षा और डिजिटल फोरेंसिक के क्षेत्र में विश्वस्तरीय विशेषज्ञता विकसित की है तथा देश के अनेक बैंकों को पेशेवर सेवाएं उपलब्ध करा रहा है। एनयूसीएफडीसी और एनएफएसयू के बीच यह साझेदारी शहरी सहकारी बैंकों तथा उनके ग्राहकों की डिजिटल सुरक्षा को और मजबूत करेगा।**

करेगा। इससे शहरी सहकारी बैंक आधुनिक बैंकिंग प्रतिस्पर्धा में अन्य बैंकों के साथ समान स्तर पर खड़े हो सकेंगे। इससे शहरी सहकारी बैंकिंग आंदोलन को नया जीवन मिलेगा, उसकी पहुंच का विस्तार होगा तथा बैंकिंग सेवाएं आधुनिक, पारदर्शी और विश्वसनीय बनेंगी। श्री शाह ने इस अवसर पर 'बैंक इन बॉक्स' सेवा का भी शुभारंभ किया। इसके माध्यम से शहरी सहकारी बैंकों को कोर बैंकिंग, डिजिटल भुगतान, क्लाउड सेवाएं, नियामकीय अनुपालन तथा आधुनिक बैंकिंग से जुड़ी अनेक सुविधाएं एक ही एकीकृत प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होंगी। इससे एक शाखा वाला छोटा शहरी सहकारी बैंक भी बिना अधिक खर्च किए अपने ग्राहकों को आधुनिक और विश्वस्तरीय बैंकिंग सुविधाएं प्रदान कर सकेगा। यह पहल छोटे बैंकों को तकनीकी रूप से सक्षम बनाने और उन्हें प्रतिस्पर्धी बैंकिंग व्यवस्था से जोड़ने का मार्ग प्रशस्त करेगी।

साइबर सुरक्षा भी मिलेगी

ऑनलाइन बैंकिंग के वर्तमान दौर में फोरेंसिक विज्ञान के सहयोग के बिना न तो बैंक पूरी तरह सुरक्षित रह सकते हैं और न ही उनके ग्राहक। इसी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए एनयूसीएफडीसी को राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय (एनएफएसयू) के साथ समझौता ज्ञापन करने का सुझाव दिया गया था। इस कार्यक्रम में दोनों के बीच एमओयू भी हुआ। एनएफएसयू ने साइबर सुरक्षा और डिजिटल फोरेंसिक के क्षेत्र में विश्वस्तरीय विशेषज्ञता विकसित की है तथा देश के अनेक बैंकों को पेशेवर सेवाएं उपलब्ध करा रहा है। एनयूसीएफडीसी और एनएफएसयू के बीच यह साझेदारी शहरी सहकारी बैंकों तथा उनके ग्राहकों की डिजिटल सुरक्षा को और मजबूत करेगा। इस समझौते के माध्यम से छोटे से छोटे शहरी सहकारी बैंक की प्रत्येक शाखा तक साइबर सुरक्षा और डिजिटल फोरेंसिक से

जुड़ी सुविधाएं अत्यंत कम लागत पर पहुंचाई जाएंगी। साइबर सुरक्षा, डिजिटल फोरेंसिक, इन क्षेत्रों में कर्मचारियों के प्रशिक्षण तथा अनुसंधान की व्यवस्थाएं 'बैंक इन बॉक्स' के माध्यम से एकीकृत रूप में उपलब्ध होंगी। जबकि सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर शहरी सहकारी बैंकों को चौबीसों घंटे साइबर निगरानी, त्वरित मार्गदर्शन और सुरक्षा प्रदान करेगा।

सभी शहरी सहकारी बैंकों से इस सेंटर का सदस्य बनने का आग्रह करते हुए श्री अमित शाह ने कहा कि डिजिटल खतरों से बैंकों, ग्राहकों और जमाकताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए इसकी सदस्यता अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने स्पष्ट किया कि अंब्रेला ऑर्गेनाइजेशन का उद्देश्य लाभ कमाना नहीं, बल्कि शहरी सहकारी बैंकों को सुव्यवस्थित करना, राष्ट्रीय और वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार करना तथा संकट के समय उनकी सहायता करना है।

देशभर में 1400 शहरी सहकारी बैंक

देशभर में इस समय लगभग 1,400 शहरी सहकारी बैंक हैं जिनमें करीब 6 लाख करोड़ रुपये की जमाराशि है। इन बैंकों की देश के विकास में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका है। छोटे दुकानदारों, व्यापारियों, कुटीर उद्योगों, एमएसएमई, स्थानीय उद्यमियों, महिला स्वयं सहायता समूहों और मध्यम वर्ग के लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए छोटे ऋण उपलब्ध कराने का कार्य शहरी सहकारी बैंक प्रभावी ढंग से करते हैं। बड़े वाणिज्यिक बैंकों के लिए समाज के इन वर्गों तक उसी निकटता और संवेदनशीलता के साथ पहुंचना संभव नहीं होता। तहसील स्तर पर स्थापित एक शहरी सहकारी बैंक पूरे क्षेत्र में रोजगार और स्वरोजगार से जुड़े लोगों की वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने का माध्यम बनता है। छोटे ऋणों में पुनर्भुगतान की प्रवृत्ति अत्यंत मजबूत होती है क्योंकि सामान्य और छोटे आय वर्ग के ग्राहक अपने दायित्वों के प्रति अधिक ईमानदार होते हैं।

अमित शाह भी शहरी सहकारी बैंक के चेयरमैन रहे हैं। अपना अनुभव साझा करते हुए उन्होंने बताया कि उनके बैंक ने बिना गारंटी और बिना किसी कोलेटरल के ढाई लाख रुपये तक का कर्ज देने का निर्णय लिया था। बिना गारंटी और बिना कोलेटरल के छोटे कर्ज देने की यह योजना आज भी जारी है। इसकी सीमा ढाई लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दी गई है। इस योजना के अंतर्गत वितरित ऋणों में लगभग पूरे पैसे की रिकवरी ब्याज सहित वापस आई है। शेष अत्यंत सीमित मामलों में ऋण न लौटने का कारण ग्राहकों की मृत्यु जैसी असाधारण परिस्थितियां रही हैं। श्री शाह ने कहा कि यह अनुभव प्रमाणित करता है कि ऋण जितना

पारदर्शिता से ही होगा विस्तार

अमित शाह ने कहा कि देश के सभी 1,400 शहरी सहकारी बैंकों को अपने कामकाज में पारदर्शिता लानी होगी, आधुनिक प्रौद्योगिकी अपनानी होगी, कर्मचारियों को प्रशिक्षित करना होगा और ग्राहकों को सभी प्रकार की आधुनिक बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध करानी होंगी, ताकि वे प्रतिस्पर्धा में बने रहने के साथ-साथ अपना विस्तार भी कर सकें। वर्तमान में 1,400 शहरी सहकारी बैंकों में से 650 बैंक अंब्रेला ऑर्गेनाइजेशन के सदस्य बन चुके हैं और सदस्यता लगभग 50 प्रतिशत तक पहुंची है। उन्होंने एनयूसीएफडीसी से छोटे और एक शाखा वाले बैंकों की सुविधा के अनुरूप सदस्यता शुल्क को और किफायती बनाने की अपेक्षा व्यक्त की। अमित शाह ने देशभर के शहरी सहकारी बैंक महासंघों के अध्यक्षों और पदाधिकारियों से आह्वान किया कि वे अगले एक वर्ष के भीतर शत-प्रतिशत शहरी सहकारी बैंकों को अंब्रेला ऑर्गेनाइजेशन के नेटवर्क से जोड़ने की जिम्मेदारी निभाएं। उन्होंने कहा कि भारत को समृद्ध बनाने के लिए प्रत्येक भारतीय को समृद्ध बनाना आवश्यक है। केवल पूंजी बाजार के माध्यम से प्रत्येक नागरिक तक समृद्धि नहीं पहुंच सकती, इसके लिए देश में स्वरोजगार की एक व्यापक और मजबूत व्यवस्था खड़ी करनी होगी। शहरी सहकारी बैंक छोटे व्यापारियों, उद्यमियों और स्वरोजगार से जुड़े लोगों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराकर इस व्यवस्था को सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।

'सहकार नव-क्रांति' कार्यक्रम में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस, महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे, केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री श्री कृष्ण पाल गुर्जर एवं श्री मुरलीधर मोहोल, महाराष्ट्र के सहकारिता मंत्री श्री बाबासाहेब पाटील, सहकारिता मंत्रालय के सचिव श्री आशीष कुमार भूटानी, एनयूसीएफडीसी के अध्यक्ष श्री ज्योतिन्द्र मेहता सहित विभिन्न राज्यों के शहरी सहकारी बैंक महासंघों के प्रतिनिधि तथा देशभर के शहरी सहकारी बैंकों से जुड़े अनेक गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।

देशभर में इस समय लगभग 1,400 शहरी सहकारी बैंक हैं जिनमें करीब 6 लाख करोड़ रुपये की जमाराशि है। छोटे दुकानदारों, व्यापारियों, कुटीर उद्योगों, एमएसएमई, स्थानीय उद्यमियों, महिला स्वयं सहायता समूहों और मध्यम वर्ग के लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए छोटे ऋण उपलब्ध कराने का कार्य शहरी सहकारी बैंक प्रभावी ढंग से करते हैं।

सुविधा विस्तार से ज्यादा सक्षम बने यूसीबी

एनपीए खातों से संबंधित प्रावधानों के अनुपालन के लिए शहरी सहकारी बैंकों को चरणबद्ध 'ग्लाइड पाथ' उपलब्ध कराया गया है, जिससे बैंकों पर एक ही वर्ष में पूरा वित्तीय भार न पड़े। पहले केवल वाणिज्यिक और राष्ट्रीयकृत बैंकों को उपलब्ध वन टाइम सेटलमेंट की सुविधा अब शहरी सहकारी बैंकों को भी प्रदान की गई है। व्यक्तिगत आवास ऋण की सीमा बढ़ाने के साथ लाइसेंस संबंधी शुल्क में भी कमी की गई है। शहरी सहकारी बैंकों, राज्य सहकारी बैंकों और जिला सहकारी बैंकों को 'मेंबर लेडिंग इंस्टीट्यूशन' का दर्जा दिया गया है जिससे 85 प्रतिशत तक जोखिम कवरेज और कोलेटरल मुक्त ऋण की सुविधा उपलब्ध हो सकेगी। इसके अतिरिक्त सहकारी समितियों के लिए प्राथमिकता क्षेत्र ऋण की सीमा 5 लाख रुपये से बढ़ाकर 10 करोड़ रुपये की गई है। इन सुधारों से शहरी सहकारी बैंक अपनी वित्तीय पहुंच बढ़ाने, ग्राहकों को बेहतर ऋण सुविधाएं देने और आधुनिक बैंकिंग व्यवस्था में प्रभावी रूप से प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम होंगे।

आधुनिक बैंकिंग के लिए डिजिटल बैंकिंग, रियल-टाइम भुगतान, साइबर और डेटा सुरक्षा, एआई (कृत्रिम बुद्धिमत्ता) आधारित धोखाधड़ी रोकथाम प्रणाली तथा नियामकीय मानकों की पूर्ति में अंब्रेला ऑर्गेनाइजेशन शहरी सहकारी बैंकों की सहायता करेगा। महाराष्ट्र में देश के सर्वाधिक 449 शहरी सहकारी बैंक हैं।

छोटा होता है, उसकी वसूली उतनी ही बेहतर होती है। छोटे कर्जधारक अपने वित्तीय दायित्वों के प्रति अत्यंत ईमानदार होते हैं।

छोटी पूंजी बड़ा बिजनेस

भारत की अर्थव्यवस्था में स्वरोजगार के अवसर पैदा करने में सहकारिता की बहुत बड़ी भूमिका है। बड़े व्यापार के लिए केवल किसी एक व्यक्ति की बड़ी पूंजी आवश्यक नहीं होती। छोटे-छोटे लोगों को सहकारिता के माध्यम से जोड़कर, उनकी छोटी-छोटी पूंजी को एकत्रित कर बड़ी पूंजी का निर्माण किया जा सकता है और उसके आधार पर बड़े व्यावसायिक संस्थान खड़े किए जा सकते हैं। यही सहकारिता की मूल शक्ति है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने अमूल, इफको, कृभको और लिज्जत पापड़ का उदाहरण देते हुए कहा कि इन संस्थाओं की सफलता किसी एक बड़े पूंजी निवेशक के कारण नहीं, बल्कि लाखों छोटे सदस्यों की सामूहिक भागीदारी से संभव हुई है। अमूल आज लगभग एक लाख 25 हजार करोड़ रुपये का कारोबार करता है और इसमें करीब 33 लाख महिलाओं की हिस्सेदारी है। यह उदाहरण दर्शाता है कि सहकारिता छोटी पूंजी और व्यापक जनभागीदारी को जोड़कर एक बड़ी आर्थिक शक्ति में बदल सकती है।

मुंबई ट्रांसफर होगा एनयूसीएफडीसी मुख्यालय

आधुनिक बैंकिंग के लिए डिजिटल बैंकिंग, रियल-टाइम भुगतान, साइबर और डेटा सुरक्षा, एआई (कृत्रिम बुद्धिमत्ता) आधारित धोखाधड़ी रोकथाम प्रणाली तथा नियामकीय मानकों की पूर्ति में अंब्रेला ऑर्गेनाइजेशन शहरी सहकारी बैंकों की सहायता करेगा। महाराष्ट्र में देश के सर्वाधिक 449 शहरी सहकारी बैंक हैं। महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा और कर्नाटक मिलकर देश के अधिकांश शहरी सहकारी बैंकों का प्रतिनिधित्व करते हैं। श्री शाह ने

बताया कि इन राज्यों में शहरी सहकारी बैंकों की गतिविधियों और मौजूदगी को देखते हुए एनयूसीएफडीसी का मुख्यालय दिल्ली से महाराष्ट्र स्थानांतरित किया जाएगा। एनयूसीएफडीसी की अवधारणा पूरी तरह स्पष्ट है– शहरी सहकारी बैंकों को तकनीकी अवसंरचना, साइबर सुरक्षा, भुगतान प्रणाली और आधुनिक बैंकिंग सुविधाएं अत्यंत किफायती लागत पर उपलब्ध कराना। यदि देश के सभी 1,400 शहरी सहकारी बैंक इन सेवाओं, सॉफ्टवेयर और तकनीकी व्यवस्थाओं को अलग-अलग खरीदें तथा उनका रखरखाव स्वयं करें, तो इसकी लागत बहुत अधिक होगी। इसके विपरीत, अंब्रेला ऑर्गेनाइजेशन सभी बैंकों की ओर से सामूहिक अनुबंध करेगा, आवश्यक सॉफ्टवेयर खरीदेगा और उनके रखरखाव की जिम्मेदारी संभालेगा, जिससे लागत में बड़ी कमी आएगी और छोटे बैंक भी आधुनिक तकनीक का लाभ उठा सकेंगे।

आरबीआई ने किया समाधान

अंब्रेला फ्रेमवर्क और नए कार्यालय के शुभारंभ के साथ सहकार सीबीएस, साझा भुगतान सेवाएं, लोन ओरिजिनेशन प्रणाली, सहकार क्लाउड और सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर जैसी अनेक सेवाओं को एक साथ आगे बढ़ाया जाएगा। इसके अतिरिक्त म्यूल हंटर और अन्य एआई आधारित प्रणालियां, सामूहिक साइबर बीमा, एनएफएसयू के सहयोग से छोटी से छोटी बैंक तक डिजिटल फोरेंसिक क्षमता का विस्तार, आधार आधारित सेवाएं, नियामकीय अनुपालन का स्वचालन तथा जोखिम प्रबंधन की आधुनिक व्यवस्था विकसित की जाएगी। ये सभी पहल शहरी सहकारी बैंकों को अधिक सुरक्षित, सक्षम, पारदर्शी और प्रतिस्पर्धी बनाएंगी। पिछले पांच वर्षों में सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक के बीच विश्वास और संवाद के आधार पर शहरी सहकारी बैंकों से संबंधित अनेक मुद्दों का समाधान किया गया है। इनमें बिना अलग अनुमति के 15 प्रतिशत तक शाखाएं खोलने, डोरस्टेप बैंकिंग, पात्र टियर-3 बैंकों के लिए शेड्यूल्ड बैंक का दर्जा प्राप्त करने की प्रक्रिया को सरल बनाने, आरबीआई में नोडल अधिकारी की नियुक्ति, प्राथमिकता क्षेत्र ऋण लक्ष्य को 75 प्रतिशत से घटाकर 60 प्रतिशत करने, आवास ऋण सीमा बढ़ाने और वन टाइम सेटलमेंट की सुविधा देने जैसे निर्णय शामिल हैं।■

अंब्रेला फ्रेमवर्क और नए कार्यालय के शुभारंभ के साथ सहकार सीबीएस, साझा भुगतान सेवाएं, लोन ओरिजिनेशन प्रणाली, सहकार क्लाउड और सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर जैसी अनेक सेवाओं को एक साथ आगे बढ़ाया जाएगा।

लाल किले की प्राचीर से बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी

युवा शक्ति और सहकार से बनेगा विकसित भारत

सहकारिता से मजबूत होगी ग्रामीण अर्थव्यवस्था, रोजगार और स्टार्टअप पर सरकार का फोकस

2047 के भारत का केंद्र बनेगा युवा, युवा बनेंगे विकसित भारत की धुरी

युवा सहकार टीम

80वें स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन विकसित भारत के संकल्प के साथ देश की युवा शक्ति को केंद्र में रखने वाला रहा। 15 अगस्त के अपने भाषण में प्रधानमंत्री ने साफ संदेश दिया कि 2047 तक विकसित भारत के निर्माण में युवाओं की भूमिका केवल लाभार्थी की नहीं, बल्कि नेतृत्वकर्ता की होगी। उन्होंने भरोसा जताया कि विकसित भारत का सबसे बड़ा लाभ देश के युवाओं को मिलेगा। इसलिए युवाओं को अवसर, कौशल, रोजगार, तकनीक, नवाचार और खेल के नए क्षेत्रों से जोड़ना राष्ट्रीय प्राथमिकता होनी चाहिए।

80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर उन्होंने 2047 के भारत की तस्वीर सामने रखते हुए कहा कि देश को अपनी क्षमता, संकल्प और नागरिकों की भागीदारी के बल पर विकसित राष्ट्र बनना है। उनके भाषण में युवाओं के लिए किए गए ऐलान इसी बड़ी सोच का हिस्सा दिखाई दिए। एक ऐसा भारत, जहां युवा नई तकनीक सीखे, रोजगार पाए, खुद उद्यम शुरू करे, दूसरों को रोजगार दे, खेलों में देश का नाम रोशन करे और ग्रामीण तथा स्थानीय अर्थव्यवस्था की मजबूती में भी भागीदार बने।

प्रधानमंत्री के पूरे संबोधन को युवा और सहकारिता के दृष्टिकोण से देखें तो एक महत्वपूर्ण तस्वीर उभरती है। भाषण में सहकारिता क्षेत्र के लिए भले ही किसी नई योजना की घोषणा नहीं की गई, लेकिन स्थानीय उत्पादन, एमएसएमई, महिलाओं का आर्थिक सशक्तीकरण, ग्रामीण अर्थव्यवस्था, रोजगार और उद्यमिता पर जिस तरह जोर दिया गया, उसमें सहकार आधारित विकास की व्यापक संभावनाएं मौजूद हैं। गांवों में सामूहिक उत्पादन करने वाले समूह, छोटे उत्पादक, महिला स्वयं सहायता समूह और स्थानीय उद्यम यदि तकनीक और प्रशिक्षित युवाओं से जुड़ते हैं, तो सहकारिता नई अर्थव्यवस्था में और प्रभावी भूमिका निभा सकती है।

एक साल में एक करोड़ युवाओं को एआई की ट्रेनिंग

प्रधानमंत्री के भाषण में युवाओं से जुड़ी सबसे बड़ी घोषणाओं में एक वर्ष के भीतर एक करोड़ युवाओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई स्किल्स में प्रशिक्षित करने का लक्ष्य प्रमुख रहा। प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया तेजी से एआई की ओर बढ़ रही है और भारत के युवाओं को इस तकनीकी बदलाव में पीछे नहीं रहना चाहिए। उनका लक्ष्य है कि भारतीय युवा केवल तकनीक का इस्तेमाल करने वाले न हों, बल्कि दुनिया में एआई के क्षेत्र में नेतृत्व करने की क्षमता भी विकसित करें।

यह पहल केवल आईटी सेक्टर तक सीमित नहीं मानी जा सकती। आने वाले समय में एआई का उपयोग कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, वित्त, परिवहन, बाजार प्रबंधन, विनिर्माण, लॉजिस्टिक्स और ग्रामीण उद्यमों तक बढ़ना तय है। ऐसे में यदि ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं को भी तकनीकी कौशल से जोड़ा जाता है तो वे स्थानीय सहकारी संस्थाओं और सामूहिक उद्यमों को आधुनिक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।

उदाहरण के तौर पर, किसानों के सहकारी समूह बाजार की मांग का विश्लेषण कर सकते हैं, उत्पादकों को डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़ा जा सकता है, महिला समूह ऑनलाइन बिक्री कर सकते हैं और स्थानीय उत्पादों की ब्रांडिंग तथा मार्केटिंग आधुनिक तरीके से की जा सकती है। यानी प्रधानमंत्री का एआई स्किलिंग का लक्ष्य केवल नौकरियां पैदा करने तक सीमित न रहकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को तकनीक से जोड़ने की क्षमता भी रखता है।

युवाओं के लिए मुफ्त ऑनलाइन कोचिंग

प्रधानमंत्री ने प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले युवाओं के लिए मुफ्त ऑनलाइन कोचिंग नेटवर्क तैयार करने की भी घोषणा की। उन्होंने कहा कि गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों पर निजी कोचिंग का खर्च बड़ा आर्थिक बोझ बनता है। इसलिए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, देश में उपलब्ध अच्छे शिक्षकों और प्रतिभाओं को एक साथ लाकर युवाओं के लिए मुफ्त तैयारी की व्यवस्था विकसित की जाएगी।

यह घोषणा गांव और छोटे शहरों के युवाओं के लिए विशेष महत्व रखती है। बड़े शहरों में उपलब्ध शिक्षण संसाधनों तक हर छात्र नहीं पहुंच पाता। ऑनलाइन नेटवर्क इस दूरी को कम कर सकता है। सहकारी संस्थाएं और सामुदायिक संगठन भी इस प्रयास को स्थानीय स्तर पर मजबूत करने में सहयोगी बन सकते हैं। गांवों में साझा डिजिटल अध्ययन केंद्र, इंटरनेट सुविधाएं और अध्ययन संसाधन उपलब्ध कराए जाएं तो ऐसे युवाओं को भी अवसर मिल सकता है, जिनके घरों में पर्याप्त डिजिटल साधन नहीं हैं।

गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों पर निजी कोचिंग का खर्च बड़ा आर्थिक बोझ बनता है। इसलिए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, देश में उपलब्ध अच्छे शिक्षकों और प्रतिभाओं को एक साथ लाकर युवाओं के लिए मुफ्त तैयारी की व्यवस्था विकसित की जाएगी।

2036 ओलंपिक के लक्ष्य में भी युवाओं पर फोकस

प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में खेलों को भी युवा भारत के भविष्य से जोड़ा। उन्होंने कहा कि खेलों में भारत का प्रदर्शन लगातार बेहतर हो रहा है और देश 2036 ओलंपिक की मेजबानी के लिए मजबूत दावेदार के रूप में आगे बढ़ रहा है। साथ ही उन्होंने 2030 के राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी का भी उल्लेख किया। इस लक्ष्य के लिए प्रधानमंत्री ने गांवों, शहरों और स्कूलों में 5 से 15 वर्ष के बच्चों की खेल प्रतिभा की पहचान करने के लिए देशव्यापी टैलेंट हंट की घोषणा की। इसका उद्देश्य ऐसे बच्चों को पहचानना है, जिनमें भविष्य के अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी बनने की क्षमता है और फिर उन्हें विशेष प्रशिक्षण उपलब्ध कराना है। खेल की इस नई व्यवस्था में भी स्थानीय सामुदायिक और सहकारी संस्थाओं की भूमिका संभावित रूप से महत्वपूर्ण हो सकती है। गांवों में खेल मैदान, स्थानीय प्रतियोगिताएं और प्रशिक्षण सुविधाएं उपलब्ध कराने में सामूहिक भागीदारी बढ़े तो दूरदराज के क्षेत्र की प्रतिभाएं भी सामने आ सकती हैं। खेल स्वयं भी रोजगार का बड़ा क्षेत्र बन रहा है। कोचिंग, फिटनेस, स्पोर्ट्स मेडिसिन, न्यूट्रिशन, खेल प्रबंधन और उपकरण निर्माण जैसे क्षेत्रों में युवाओं के लिए नए अवसर बन सकते हैं।

प्रधानमंत्री मोदी के 80वें स्वतंत्रता दिवस के भाषण से एक बात स्पष्ट रूप से सामने आई है कि 2047 के विकसित भारत का केंद्र युवा है। एक करोड़ युवाओं को एआई स्किलिंग, मुफ्त ऑनलाइन कोचिंग, रोजगार के नए अवसर, स्टार्टअप और इनोवेशन, खेल प्रतिभा की पहचान और नई तकनीकों में नेतृत्व जैसे कदम युवा शक्ति को भविष्य की अर्थव्यवस्था के लिए तैयार करने की दिशा दिखाते हैं। इसके साथ ग्रामीण अर्थव्यवस्था, लखपति दीदी, स्थानीय उत्पादन, एमएसएमई और वोकल फॉर लोकल पर जोर सहकारिता के लिए अवसरों का एक विस्तृत क्षेत्र खोलता है।

प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में युवाओं के लिए प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना शुरू करने का भी उल्लेख किया। लगभग एक लाख करोड़ रुपये की इस योजना के तहत निजी क्षेत्र में नौकरी पाने वाले युवाओं को 15 हजार रुपये तक की सहायता और अधिक रोजगार पैदा करने वाली कंपनियों को प्रोत्साहन देने का प्रावधान किया जाएगा।

रोजगार देने वाले बनें युवा

प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में देश के स्टार्टअप इकोसिस्टम का विशेष उल्लेख करते हुए कहा कि भारत में 2.5 लाख से अधिक पंजीकृत स्टार्टअप हैं। उन्होंने युवाओं की इस भूमिका को रेखांकित किया कि वे केवल अपने लिए रोजगार नहीं खोज रहे, बल्कि दूसरों के लिए भी रोजगार पैदा कर रहे हैं। इसके साथ प्रधानमंत्री ने एक लाख करोड़ रुपये के इनोवेशन फंड का उल्लेख करते हुए युवाओं से अपने सपने और नए विचार लेकर आगे आने को कहा। यह संदेश युवा भारत के बदलते चरित्र को दशार्ता है। नौकरी की तलाश करने वाला युवा अब स्टार्टअप, इनोवेशन और नए कारोबार के जरिए रोजगार देने वाला भी बन रहा है। सहकारिता इस उद्यमिता को गांवों और छोटे शहरों तक ले जाने का एक प्रभावी माध्यम बन सकती है। खेती, डेयरी, खाद्य प्रसंस्करण, हस्तशिल्प, स्थानीय सेवाओं, पर्यटन और डिजिटल कारोबार जैसे क्षेत्रों में युवा आधारित सहकारी उद्यम नए रोजगार पैदा कर सकते हैं।

रोजगार योजना से निजी क्षेत्र भी जुड़े

प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में युवाओं के लिए प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना शुरू करने का भी उल्लेख किया। लगभग एक लाख करोड़ रुपये की इस योजना के तहत निजी क्षेत्र में नौकरी पाने वाले युवाओं को 15 हजार रुपये तक की सहायता और अधिक रोजगार पैदा करने वाली कंपनियों को प्रोत्साहन देने का प्रावधान किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने इसे लगभग 3.5 करोड़ युवाओं के लिए रोजगार अवसर तैयार करने की दिशा में बड़ी पहल के रूप में रखा। यह घोषणा इस बात की ओर संकेत करती है कि युवाओं के रोजगार के लिए केवल सरकारी नौकरियों पर निर्भर रहने की बजाय निजी उद्योग, एमएसएमई, स्टार्टअप और उद्यमिता को भी मजबूत किया जाएगा। इसी ढांचे में सहकारी क्षेत्र भी स्थानीय रोजगार का महत्वपूर्ण स्रोत बन सकता है। गांवों में यदि कृषि प्रसंस्करण, डेयरी, भंडारण, लॉजिस्टिक्स और स्थानीय उत्पादन से जुड़े सहकारी उद्यम मजबूत होते हैं तो युवाओं का पलायन कम करने और स्थानीय आय बढ़ाने में मदद मिल सकती है।

'वोकल फॉर लोकल' से वैश्विक बाजार तक

प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में मेक इन इंडिया, स्वदेशी और वोकल फॉर लोकल को भी विकसित भारत की आर्थिक रणनीति से जोड़ा। उन्होंने भारतीय एमएसएमई और उद्यमियों को वैश्विक बाजारों में अवसर तलाशने, गुणवत्ता बढ़ाने और भारतीय उत्पादों को भरोसेमंद वैश्विक पहचान दिलाने का आह्वान किया। उनका जोर था कि भारत केवल बड़े उत्पाद ही नहीं, पूरी वैल्यू चेन देश में विकसित करे और वैश्विक सप्लाई चेन का विश्वसनीय केंद्र बने। यह संदेश सहकारी क्षेत्र के लिए विशेष महत्व रखता है। देश के लाखों कारीगर, बुनकर, किसान और छोटे उत्पादक अकेले वैश्विक बाजार तक नहीं पहुंच सकते, लेकिन सामूहिक संगठन उन्हें यह ताकत दे सकता है। इसमें युवा नई भूमिका निभा सकते हैं। वे डिजिटल मार्केटिंग संभाल सकते हैं, ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म विकसित कर सकते हैं, पैकेजिंग और ब्रांडिंग सुधार सकते हैं और बाजार के नए अवसर तलाश सकते हैं। यदि सहकारी मॉडल और युवा तकनीकी क्षमता से जुड़ता है तो गांव के उत्पाद को दुनिया के बाजार तक पहुंचाने की मजबूत व्यवस्था तैयार हो सकती है।■

चिंताजनक बेरोजगारी

युवा सहकार टीम

दुनिया की सबसे बड़ी युवा आबादी वाले देशों में शामिल भारत के लिए यही जनसांख्यिकीय बढ़त आने वाले दशकों में आर्थिक विकास, नवाचार और उत्पादन की सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। लेकिन नीति आयोग की हालिया रिपोर्ट 'विकसित भारत@2047 के लिए कौशल विकास की पुनर्कल्पना' ने इस संभावित ताकत के सामने खड़ी एक गंभीर चुनौती की ओर ध्यान खींचा है। यह चुनौती है बढ़ती बेरोजगारी जो युवाओं के लिए ही नहीं, बल्कि देश के लिए भी चिंताजनक स्थिति है।

नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार, देश में 15-29 वर्ष आयु वर्ग के लगभग 8.7 करोड़ युवा ऐसे हैं जो न पढ़ाई कर रहे हैं, न किसी रोजगार में हैं और न ही किसी तरह का प्रशिक्षण ले रहे हैं। यह केवल बेरोजगारी का आंकड़ा नहीं है। इसके पीछे शिक्षा से बाहर होना, कौशल की कमी, आर्थिक दबाव, स्थानीय स्तर पर अवसरों का अभाव और उद्योग की मांग तथा शिक्षा के बीच बढ़ती दूरी जैसी कई समस्याएं जुड़ी हुई हैं।

यह आंकड़ा क्यों महत्वपूर्ण है

नीति आयोग का यह अनुमान राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के 78वें दौर के आंकड़ों पर आधारित है। युवा आर्थिक रूप से निष्क्रिय होने के साथ-साथ भविष्य की उत्पादक अर्थव्यवस्था से भी धीरे-धीरे दूर हो सकते हैं। 15 से 29 वर्ष की उम्र व्यक्ति के जीवन का वह समय होता है जब वह पढ़ाई पूरी करता है, कौशल अर्जित करता है और श्रम बाजार में प्रवेश करता है। ऐसे में यदि इतनी बड़ी आबादी शिक्षा, प्रशिक्षण और रोजगार तीनों से बाहर है, तो इसका असर केवल व्यक्तिगत आय पर नहीं पड़ता। इसका सीधा संबंध देश की उत्पादकता, घरेलू आय, उपभोग, सामाजिक

सुरक्षा और आर्थिक विकास से भी है। यही कारण है कि नीति आयोग ने युवाओं को मुख्यधारा से जोड़ने के लिए केवल रोजगार उपलब्ध कराने की बात नहीं की है, बल्कि रोजगार से जुड़े कौशल और आर्थिक सहायता पर भी जोर दिया है।

डिग्री और नौकरी के बीच बढ़ती दूरी

नीति आयोग की रिपोर्ट में एक और महत्वपूर्ण तथ्य सामने आया है। इसके मुताबिक केवल 8.25 प्रतिशत स्नातक अपनी शैक्षणिक योग्यता के अनुरूप रोजगार में हैं। यह आंकड़ा भारतीय उच्च शिक्षा और रोजगार बाजार के बीच मौजूद असंतुलन की ओर संकेत करता है। बड़ी संख्या में युवा कॉलेज और विश्वविद्यालय से डिग्री लेकर निकल रहे हैं, लेकिन जिस विषय में उन्होंने पढ़ाई की है, उसी के अनुरूप काम मिलना मुश्किल हो रहा है। इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। कई पाठ्यक्रमों में व्यावहारिक प्रशिक्षण की कमी है। उद्योग तेजी से बदल रहा है, लेकिन पाठ्यक्रम उसी गति से नहीं

नीति आयोग ने 15-29 वर्ष के 8.7 करोड़ युवाओं की बेरोजगारी और कौशल में कमी पर जताई चिंता

केवल 8.25 प्रतिशत स्नातक अपनी शैक्षणिक योग्यता के अनुसार पाते हैं रोजगार

2014-15 से अब तक 7.67 करोड़ से अधिक युवाओं को मिल चुका है कौशल प्रशिक्षण

15 से 29 वर्ष की उम्र व्यक्ति के जीवन का वह समय होता है जब वह पढ़ाई पूरी करता है, कौशल अर्जित करता है और श्रम बाजार में प्रवेश करता है। ऐसे में यदि इतनी बड़ी आबादी शिक्षा, प्रशिक्षण और रोजगार तीनों से बाहर है तो इसका असर केवल व्यक्तिगत आय पर नहीं पड़ता। इसका सीधा संबंध देश की उत्पादकता, घरेलू आय, उपभोग, सामाजिक सुरक्षा और आर्थिक विकास से भी है।

बदलते। डिजिटल तकनीक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इलेक्ट्रिक वाहन, ग्रीन एनर्जी, ऑटोमेशन और आधुनिक विनिर्माण जैसे क्षेत्रों में कंपनियों को ऐसे युवाओं की जरूरत है जिन्हें केवल सैद्धांतिक ज्ञान नहीं बल्कि काम करने का वास्तविक अनुभव भी हो। यही वजह है कि डिग्रीधारी युवा कई बार अपनी योग्यता से कम स्तर की नौकरी स्वीकार करने को मजबूर हो जाते हैं।

कम आय वाले परिवारों पर दोहरा दबाव

कौशल विकास की सबसे बड़ी बाधाओं में पैसा भी शामिल है। कम आय वाले परिवारों के छात्रों पर पहले ही कॉलेज फीस, किताबों, आवागमन और निजी ट्यूशन का खर्च होता है। ऐसे परिवारों के लिए अलग से किसी कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम की फीस देना आसान नहीं होता। कई युवा स्नातक होने के बाद तुरंत कमाई शुरू करना चाहते हैं ताकि परिवार की मदद कर सकें। ऐसे में वे अतिरिक्त छह महीने या एक साल के प्रशिक्षण में समय और पैसा लगाने की स्थिति में नहीं होते। परिणाम यह होता है कि वे कम वेतन वाली स्थिर नौकरी स्वीकार कर लेते हैं, भले ही उनकी शैक्षणिक योग्यता उससे कहीं अधिक हो। इसी समस्या को देखते हुए नीति आयोग ने कम लागत या सब्सिडी वाले प्रशिक्षण के साथ-साथ जरूरतमंद युवाओं के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने की बात कही है।

कौशल प्रशिक्षण तभी प्रभावी होगा जब वह रोजगार की वास्तविक मांग से जुड़ा हो। यदि किसी जिले में खाद्य प्रसंस्करण, पर्यटन, टेक्सटाइल, ऑटोमोबाइल या इलेक्ट्रॉनिक्स से जुड़े उद्योग हैं तो वहां के युवाओं को उन्हीं क्षेत्रों से संबंधित प्रशिक्षण देना अधिक उपयोगी होगा। इससे प्रशिक्षण समाप्त होते ही रोजगार मिलने की संभावना बढ़ सकती है। नीति आयोग ने इसी दिशा में स्थानीय मांग आधारित कौशल प्रशिक्षण पर जोर दिया है।

इसके साथ ही भविष्य के उद्योगों की जरूरतों को भी ध्यान में रखने की आवश्यकता बताई गई है। ग्रीन इंडस्ट्री, इलेक्ट्रिक वाहन, डिजिटल तकनीक, नवीकरणीय ऊर्जा और अन्य उभरते क्षेत्रों में आने वाले वर्षों में बड़ी संख्या में नए रोजगार पैदा होने की संभावना है। यदि युवाओं को समय रहते इन क्षेत्रों की जरूरत के मुताबिक प्रशिक्षित किया जाता है तो भारत अपनी युवा आबादी को वैश्विक रोजगार बाजार में प्रतिस्पर्धी बना सकता है।

इंटर्नशिप से दूर हो सकती है अनुभव की कमी

युवाओं के सामने एक बड़ी समस्या अनुभव की भी है। कंपनियां अक्सर ऐसे उम्मीदवार चाहती हैं जिन्हें काम का व्यावहारिक अनुभव

हो। लेकिन पहली नौकरी की तलाश कर रहे युवा के पास अनुभव कहां से आए? इस समस्या का एक समाधान इंटर्नशिप हो सकती है। नीति आयोग ने छोटे और मध्यम उद्योगों में इंटर्नशिप के अवसर बढ़ाने पर जोर दिया है। एमएसएमई क्षेत्र भारत में रोजगार का बड़ा स्रोत है। यदि कॉलेजों, कौशल संस्थानों और स्थानीय उद्योगों के बीच बेहतर तालमेल बनाया जाए तो छात्र पढ़ाई के दौरान ही वास्तविक कार्यस्थल का अनुभव हासिल कर सकते हैं। इससे नौकरी पाने की उनकी संभावना बढ़ सकती है और उद्योगों को भी प्रशिक्षित युवा कार्यबल उपलब्ध हो सकता है।

स्वरोजगार भी विकल्प

नीति आयोग ने अपनी रिपोर्ट में स्वरोजगार पर भी विशेष जोर दिया गया है। भारत जैसे विशाल देश में हर युवा को सरकारी या निजी क्षेत्र की नौकरी देना संभव नहीं है। इसलिए कौशल विकास की नीति का लक्ष्य केवल नौकरी दिलाना नहीं बल्कि युवाओं को अपना काम शुरू करने योग्य बनाना भी होना चाहिए। स्थानीय सेवा, कृषि प्रसंस्करण, डिजिटल सेवाएं, मरम्मत, ई-कॉमर्स, पर्यटन, खाद्य व्यवसाय और छोटे विनिर्माण जैसे क्षेत्रों में स्वरोजगार के बड़े अवसर मौजूद हैं। इसके लिए प्रशिक्षण के साथ-साथ आसान ऋण, बाजार तक पहुंच, डिजिटल प्लेटफॉर्म और व्यवसाय शुरू करने की जानकारी भी जरूरी होगी।

7.67 करोड़ को प्रशिक्षण, फिर भी चुनौती बड़ी

नीति आयोग के अनुसार, 2014-15 से अब तक 7.67 करोड़ से अधिक लोगों को कौशल प्रशिक्षण दिया जा चुका है। यह संख्या बताती है कि कौशल विकास पर पिछले वर्षों में व्यापक काम हुआ है। इसके बावजूद 8.7 करोड़ युवाओं का शिक्षा, रोजगार और प्रशिक्षण से बाहर रहना बताता है कि चुनौती केवल प्रशिक्षण की संख्या बढ़ाने की नहीं है। अब सवाल यह भी होना चाहिए कि

प्रशिक्षण के बाद कितने युवाओं को रोजगार मिला, उनकी आय कितनी बढ़ी, कितने युवाओं ने अपना व्यवसाय शुरू किया और कितने प्रशिक्षण कार्यक्रम स्थानीय उद्योगों की वास्तविक जरूरतों से जुड़े थे।

युवा बनाएंगे विकसित भारत

भारत ने 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने का लक्ष्य रखा है। इस लक्ष्य को हासिल करने में युवा आबादी सबसे बड़ी शक्ति हो सकती है, लेकिन तब जब उसे सही शिक्षा, कौशल और रोजगार के अवसर मिले। नीति आयोग की रिपोर्ट इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह केवल समस्या नहीं बताती, बल्कि नीति की दिशा भी सुझाती है।

युवाओं के लिए किफायती प्रशिक्षण, उद्योग से जुड़ा पाठ्यक्रम, इंटर्नशिप, स्थानीय रोजगार, ग्रीन और डिजिटल सेक्टर में कौशल तथा स्वरोजगार के अवसर बढ़ाना आने वाले वर्षों की प्राथमिकता होनी चाहिए। भारत के सामने चुनौती 8.7 करोड़ युवाओं की संख्या भर नहीं है। असली चुनौती यह सुनिश्चित करना है कि कोई युवा केवल इसलिए रोजगार की दौड़ से बाहर न रह जाए क्योंकि उसके पास सही कौशल, प्रशिक्षण या अवसर तक पहुंच नहीं थी। विकसित भारत की सबसे मजबूत नींव वही होगी जिसमें युवा आबादी केवल संख्या नहीं, बल्कि प्रशिक्षित, उत्पादक और आत्मनिर्भर कार्यबल में बदले।■

ग्रीन इंडस्ट्री, इलेक्ट्रिक वाहन, डिजिटल तकनीक, नवीकरणीय ऊर्जा और अन्य उभरते क्षेत्रों में आने वाले वर्षों में बड़ी संख्या में नए रोजगार पैदा होने की संभावना है। यदि युवाओं को समय रहते इन क्षेत्रों की जरूरत के मुताबिक प्रशिक्षित किया जाता है तो भारत अपनी युवा आबादी को वैश्विक रोजगार बाजार में प्रतिस्पर्धी बना सकता है।

आईसीवाईसी समिट

एआई की नैतिकता पर अंतरराष्ट्रीय युवा सहकारी नेताओं ने की चर्चा

हांगझोऊ में एशिया-पेसिफिक कोऑपरेटिव यूथ समिट 5.0 में उठाया बड़ा सवाल- तकनीक का भविष्य कौन तय करेगा और किसके लिए

युवा सहकार टीम

चीन का हांगझोऊ शहर, जहां हजारों साल पुरानी परंपरा और संस्कृति आधुनिक तकनीक और नवाचार के साथ कदमताल करती है। शायद यही वजह थी कि एशिया-पेसिफिक कोऑपरेटिव यूथ समिट 5.0 के लिए इसे चुना गया। 1 से 4 सितंबर तक 13 देशों के 130 युवा सहकारी नेता, कार्यकर्ता, नीति-निमार्ता और तकनीकी विशेषज्ञ यहां जुटे। इस समिट का सवाल यही था कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) और डिजिटल अर्थव्यवस्था के तेजी से बदलते दौर में सहकारिता अपनी भूमिका कैसे तय करेगी? इस वर्ष समिट की थीम थी- 'फ्यूचर रेडी कोऑपरेटिवः यूथ शेपिंग एथिकल एआई एंड डिजिटल इकोनॉमी' यानी भविष्य के लिए तैयार सहकारिताएं- युवा गढ़ें नैतिक एआई और डिजिटल अर्थव्यवस्था।

यह आयोजन इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस-एशिया पेसिफिक और उसकी कमेटी ऑन यूथ कोऑपरेशन (आईसीवाईसी) ने किया। इसकी मेजबानी ऑल चाइना फेडरेशन ऑफ सप्लाई एंड मार्केटिंग कोऑपरेटिव्स और झेजियांग इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड ट्रेड ने की। आईसीए-ईयू पार्टनरशिप के सहयोग से आयोजित यह सम्मेलन इसलिए भी खास था, क्योंकि यह यूथ समिट की शुरुआत के दस साल पूरे होने का अवसर था। पहला समिट 2016 में बाली में हुआ था।

उद्घाटन समारोह में चीन की सांस्कृतिक विरासत और आधुनिक तकनीक का अनोखा मेल दिखाई दिया। पारंपरिक वां यंत्र गुजहेंग की प्रस्तुति और चीनी फेस-चेंजिंग कला बियान लियान के बाद वक्ताओं ने सीधे उस चुनौती पर बात की, जो आने वाले वर्षों में सहकारी क्षेत्र की दिशा तय कर सकती है। झेजियांग इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड ट्रेड के अध्यक्ष गुओ फुचुन, आईसीए-एपी के क्षेत्रीय निदेशक बालासुब्रमणियन जी. अय्यर, चीन में यूरोपीय संघ प्रतिनिधिमंडल के कोऑपरेशन सेक्शन के टीम लीडर पियरे यवेस लुकास और ऑल चाइना फेडरेशन ऑफ सप्लाई एंड मार्केटिंग कोऑपरेटिव्स बोर्ड ऑफ सुपरवाइजर्स के अध्यक्ष अदिली वुबुली ने युवाओं को इस बहस के केंद्र में रखा।

झेजियांग प्रांत के शिक्षा विभाग के उप महानिदेशक झू होंगफेई ने एल्गोरिद्मिक पक्षपात और डिजिटल डिवाइड जैसी चुनौतियों का उल्लेख किया। उनका संदेश स्पष्ट था कि एआई पर बहस केवल तकनीकी नहीं, बल्कि सामाजिक और नैतिक भी है। जबकि अदिली वुबुली ने चेताया कि एआई का विकास यदि कुछ बड़े डिजिटल प्लेटफॉर्म और कंपनियों के हाथों में सिमटता गया तो असमानता बढ़ सकती है। उनके मुताबिक सहकारी मॉडल लोगों को केंद्र में रखकर इसका विकल्प दे सकता है, लेकिन इसके लिए सावधानी, जांच और संतुलन जरूरी होंगे। आईसीए-एपी के क्षेत्रीय निदेशक के बालासुब्रमणियन अय्यर ने इस विचार को आगे बढ़ाते हुए कहा कि एआई का विरोध करने या आंख मूंदकर उसे अपनाने की चुनौती नहीं है, बल्कि इसे जिम्मेदारी से लोगों के हित में ढालने की है।

बहस से आगे, प्रयोग की ओर

समिट की खासियत यह रही कि चर्चा केवल मंचों तक सीमित नहीं रही। प्रतिभागियों को कार्यशालाओं और नीति-अभ्यासों के जरिए समस्याओं को समझने और समाधान तैयार करने का अवसर मिला। ओपनिंग सेशन में आईसीवाईसी की चेयरपर्सन दुल्से बुस्टामांते ने कहा कि एआई कोई ऐसी शक्ति नहीं है जिसके सामने समाज को केवल समर्पण करना पड़े। इसे किस दिशा में ले जाना है, यह इंसानों को तय करना होगा। आईसीए-ईयू की प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर और आईसीवाईसी की सचिव मोनालिसा कश्यप ने युवा समिट के पिछले एक दशक और आईसीए-ईयू की साझेदारी के योगदान को रेखांकित किया।

कोऑपरेटिव स्टार्टअप की प्रयोगशाला

समिट का एक बेहद व्यावहारिक सत्र था स्टार्टअप यात्रा पर क्षमता निर्माण। आईएलओ के कोऑपरेटिव एंड सोशल एंड सॉलिडैरिटी इकोनॉमी डेवलपमेंट विशेषज्ञ रेयान कुदैह ने प्रतिभागियों को काल्पनिक सहकारी संस्थाएं बनाने का अभ्यास कराया। युवाओं ने शुरुआत से अपनी सहकारी संस्थाओं की कल्पना की कि वे क्या करेंगी, किसके लिए करेंगी, उन्हें किन चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा और उनका संचालन किस तरह होगा। इसके बाद टीमों ने अपने मॉडल सामने रखे। अलग-अलग देशों से आए प्रतिभागियों के अनुभवों ने इस अभ्यास को एक अंतरराष्ट्रीय प्रयोगशाला में बदल दिया।

इसी तरह, डिजिटल एंड एआई टूलकिट फॉर कोऑपरेटिव्स सत्र में सिंगापुर प्रोफेशनल्स एंड एक्जीक्यूटिव्स कोऑपरेटिव्स के बोर्ड सदस्य और प्रशिक्षक जिमी बोई वाई केओंग ने एआई के व्यावहारिक इस्तेमाल पर चर्चा की। सवाल सिर्फ यह नहीं था कि एआई क्या कर सकता है, बल्कि यह भी कि सहकारी संस्थाओं के काम, शासन और संचार में एआई की सीमा कहां होनी चाहिए। प्रतिभागियों ने एआई की मदद से डैशबोर्ड, वेबसाइट और न्यूजलेटर तैयार करना सीखा। यानी सत्र के अंत में वे केवल एआई के बारे में जानने वाले लोग नहीं थे, बल्कि उसका इस्तेमाल करने का व्यावहारिक अनुभव लेकर लौट रहे थे।

भविष्य की जिम्मेदारी

4 सितंबर को समिट का समापन केवल विदाई के साथ नहीं हुआ, बल्कि प्रतिभागियों ने एपीसीवाईएस 5.0 कमिटमेंट्स लॉन्च किए और गो ग्रीन कैम्पेन में हिस्सा लिया। इसके बाद उन्होंने अलीबाबा और आईफ्लाईटेक जैसी तकनीकी कंपनियों का दौरा किया। यानी जिस डिजिटल अर्थव्यवस्था पर चार दिन बहस हुई, उसे प्रत्यक्ष रूप से उन्हें देखने का मौका भी मिला। समापन समारोह में एसीएफएसएमसी के इंटरनेशनल कोऑपरेशन डिपार्टमेंट के महानिदेशक कांग शान, आईसीवाईसी के उपाध्यक्ष अभिषेक कुमार और जेलिजाबेथ कबुहाट समेत अन्य वक्ताओं ने समिट के अनुभव साझा किए। हांगझोऊ से लौटे युवा सहकारी नेताओं और कार्यकर्ताओं के पास सिर्फ नई तकनीक की जानकारी नहीं थी, बल्कि उनके पास एक बड़ा सवाल और उससे भी बड़ी जिम्मेदारी थी कि क्या एआई लोगों को नियंत्रित करने वाली तकनीक बनेगा या लोगों की सामूहिक शक्ति को मजबूत करने का माध्यम?

एशिया-पेसिफिक कोऑपरेटिव यूथ समिट 5.0 का जवाब साफ था कि भविष्य तकनीक तय नहीं करेगी। भविष्य का आकार वे लोग तय करेंगे जो तकनीक के इस्तेमाल के नियम, उसकी सीमाएं और उसके उद्देश्य तय करने में अपनी आवाज बुलंद करेंगे। सहकारिता की ताकत यही है कि उस आवाज के केंद्र में लोग हों।■

पैक्स में लागू होगी नई एचआर पॉलिसी

केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय ने पेश किया मॉडल एचआर पॉलिसी का नया मसौदा

सहकारिता क्षेत्र में नई कार्यसंस्कृति देगी दस्तक, पैक्स में आएगा प्रोफेशनल मैनेजमेंट

भर्ती में योग्यता और पारदर्शिता पर होगा जोर, कर्मचारियों के काम का हर साल होगा मूल्यांकन

युवा सहकार टीम

ग्रामीण भारत में सहकारिता की सबसे मजबूत और जमीन से जुड़ी कड़ी मानी जाने वाली प्राथमिक कृषि ऋण समितियां यानी पैक्स अब बदलाव के नए दौर की ओर बढ़ रही हैं। वर्षों तक किसान को कृषि ऋण उपलब्ध कराने, जमा स्वीकार करने और स्थानीय स्तर पर वित्तीय सेवाएं देने के लिए पहचानी जाने वाली पैक्स का दायरा अब तेजी से बढ़ रहा है। डिजिटल सेवाएं, गैर कृषि ऋण कारोबार, कृषि इनपुट, सार्वजनिक वितरण प्रणाली और दूसरी ग्रामीण सेवाओं के विस्तार के साथ उनकी भूमिका पहले से अधिक व्यापक हो रही है। इस बदलाव के बीच सबसे बड़ा सवाल मानव संसाधन का है। यदि पैक्स को आधुनिक बनाना है तो केवल तकनीक, कंप्यूटर या नए कारोबार पर्याप्त नहीं होंगे। इन्हें चलाने वाले कर्मचारियों की भर्ती, प्रशिक्षण, वेतन, प्रदर्शन, पदोन्नति और जवाबदेही की व्यवस्था भी पेशेवर होनी चाहिए। पैक्स के लिए नई एचआर (मानव संसाधन) पॉलिसी लाने का प्रस्ताव केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय ने पेश किया है। जून 2026 में तैयार मॉडल मानव संसाधन नीति के प्रस्ताव में पैक्स, लैम्पस और एफएसएस के एचआर प्रबंधन में एकरूपता, पारदर्शिता और व्यावसायिकता लाने का खाका पेश किया गया है।

जितना बड़ा कारोबार, उतनी बड़ी टीम

मॉडल एचआर नीति की प्रमुख विशेषता यह है कि हर पैक्स में कर्मचारियों की संख्या एक जैसी रखने की बजाय उसे संस्था के कारोबार और गतिविधियों से जोड़ा गया है। पिछले वित्त वर्ष के कारोबार के आधार पर पैक्स, लैम्पस और एफएसएस को ए प्लस से एफ तक सात श्रेणियों में रखने का प्रस्ताव है। इसमें ऋण, जमा, मिनी बैंक कारोबार और अन्य गैर-ऋण गतिविधियां शामिल होंगी। 10 करोड़ रुपये से अधिक कारोबार वाली ए प्लस श्रेणी में न्यूनतम सात कर्मचारी, 5 से 10 करोड़ रुपये वाली ए श्रेणी में छह, 3 से 5

करोड़ रुपये वाली बी श्रेणी में पांच और 1 से 3 करोड़ रुपये वाली सी श्रेणी में चार कर्मचारी रखने का प्रस्ताव किया गया है। 50 लाख से 1 रुपये करोड़ वाली डी श्रेणी में तीन तथा ई और एफ श्रेणी में न्यूनतम दो कर्मचारी होंगे। इस मसौदे का मूल विचार यह है कि जिस पैक्स का कारोबार बढ़े, उसकी मानव संसाधन क्षमता भी बढ़े। कारोबार बढ़ने पर अतिरिक्त क्लर्क, डीईओ, विशेषज्ञ या प्रबंधकीय पद जोड़े जा सकेंगे, लेकिन अतिरिक्त नियुक्तियों को वित्तीय रोडमैप से जोड़ते हुए तीन वर्षों के भीतर वेतन और प्रशासनिक लागत संस्था के राजस्व से पूरा करने की अपेक्षा रखी गई है।

छोटे पैक्स के लिए साझा सचिव का

सभी पैक्स का आर्थिक आकार समान नहीं है। कई छोटी समितियों के लिए अलग पूर्णकालिक सचिव रखना वित्तीय रूप से कठिन हो सकता है। इसलिए 25 लाख रुपये से कम कारोबार वाली पैक्स, लैम्पस या एफएसएस में जिला स्तरीय समिति के निर्णय के आधार पर एक सचिव को एक से अधिक समितियों का काम संभालने की अनुमति देने का प्रस्ताव है। यह व्यवस्था शुरुआती तीन वर्षों के लिए हो सकती है और आवश्यकता पड़ने पर दो वर्ष बढ़ाई जा सकती है, लेकिन कुल अवधि पांच वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। 25 लाख रुपये से अधिक कारोबार वाले पैक्स के लिए पूर्णकालिक सचिव का प्रावधान है। इससे छोटे संस्थानों में लागत दक्षता और पेशेवर प्रबंधन के बीच संतुलन साधने की कोशिश की गई है।

भर्ती में योग्यता और पारदर्शिता पर जोर

पैक्स के पेशेवर परिवर्तन की मजबूत नींव भर्ती व्यवस्था हो सकती है। सचिव और प्रबंधक जैसी प्रमुख भूमिकाओं के लिए लिखित परीक्षा को 75 प्रतिशत वेटेज, साक्षात्कार को 10 प्रतिशत और राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त सहकारिता संबंधी डिग्री या

डिप्लोमा को 15 प्रतिशत तक वेटेज देने का प्रस्ताव है। भर्ती आईबीपीएस या राज्य भर्ती बोर्ड के माध्यम से कराई जा सकती है। सचिव और प्रबंधक के लिए स्नातक योग्यता के साथ सहकारी प्रबंधन की शिक्षा को प्राथमिकता दी गई है। अकाउंटेंट या सहायक कार्यपालक के लिए भी स्नातक और सहकारी प्रबंधन से जुड़ी योग्यता को वरीयता दी जाएगी, जबकि क्लर्क या डीईओ के लिए 12वीं और कंप्यूटर दक्षता आवश्यक होगी। इसका मकसद साफ है कि भविष्य में पैक्स को ऐसे कर्मचारियों की जरूरत होगी जो पारंपरिक सहकारी कामकाज के साथ डिजिटल प्लेटफॉर्म, वित्तीय सेवाओं और आधुनिक ग्राहक सेवा को भी समझते हों। इसके लिए अभी से तैयारी करनी जरूरी है।

मौजूदा कर्मचारियों के लिए भी अपस्किलिंग

नई व्यवस्था केवल नई नियुक्तियों तक सीमित नहीं रहेगी। पहले से कार्यरत ऐसे सचिवों और सहायक कार्यपालकों के लिए भी प्रस्तावित पॉलिसी में अनुपालन का रास्ता दिया गया है जो निर्धारित न्यूनतम योग्यता पूरी

सचिव और प्रबंधक जैसी प्रमुख भूमिकाओं के लिए लिखित परीक्षा को 75 प्रतिशत वेटेज, साक्षात्कार को 10 प्रतिशत और राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त सहकारिता संबंधी डिग्री या डिप्लोमा को 15 प्रतिशत तक वेटेज देने का प्रस्ताव है। भर्ती आईबीपीएस या राज्य भर्ती बोर्ड के माध्यम से कराई जा सकती है। सचिव और प्रबंधक के लिए स्नातक योग्यता के साथ सहकारी प्रबंधन की शिक्षा को प्राथमिकता दी गई है।

> *10 करोड़ रुपये से अधिक कारोबार वाली ए प्लस श्रेणी में न्यूनतम सात कर्मचारी, 5 से 10 करोड़ रुपये वाली ए श्रेणी में छह, 3 से 5 करोड़ रुपये वाली बी श्रेणी में पांच और 1 से 3 करोड़ रुपये वाली सी श्रेणी में चार कर्मचारी रखने का प्रस्ताव किया गया है। 50 लाख से 1 रुपये करोड़ वाली डी श्रेणी में तीन तथा ई और एफ श्रेणी में न्यूनतम दो कर्मचारी होंगे।*

नहीं करते और जिनकी सेवा में दस वर्ष से अधिक समय बचा है। उन्हें नीति लागू होने के अधिकतम पांच वर्ष के भीतर आवश्यक योग्यता हासिल करनी होगी। साथ ही ई-पैक्स व्यवस्था लागू होने के बाद सचिव, प्रबंधक, लेखाकार और सहायक कार्यपालक को ई-पैक्स सॉफ्टवेयर मॉड्यूल पर प्रशिक्षण देने का प्रावधान है। यानी बदलाव का रास्ता पुराने और अनुभवी कार्यबल के कौशल और डिजिटल क्षमता निर्माण से भी होकर जाता है।

वेतन के तीन मॉडल, राज्यों को विकल्प

राज्यों की सहकारी संरचना और पैक्स की आर्थिक क्षमता अलग-अलग होती है। इसलिए मॉडल नीति में एक ही वेतन व्यवस्था थोपने की बजाय तीन विकल्प दिए गए हैं। मॉडल ए में सचिव के लिए वेतनमान 15,000 से 40,000 रुपये और 1,000 रुपये वार्षिक वृद्धि करने का प्रावधान किया गया है। जबकि मैनेजर के लिए 12,000 से 30,000 रुपये तथा अकाउंटेंट या सहायक कार्यपालक के लिए 10,000 से 25,000 रुपये का वेतनमान प्रस्तावित है। मॉडल बी निश्चित समेकित पारिश्रमिक पर आधारित है, जबकि मॉडल सी में मूल वेतन के साथ प्रदर्शन से जुड़ा परिवर्तनीय भुगतान शामिल होगा। राज्य किसी एक मॉडल या अनुमोदित हाइब्रिड व्यवस्था को अपना सकते हैं। किसी भी मॉडल में कुल पारिश्रमिक राज्य की लागू न्यूनतम मजदूरी से कम नहीं होगा।

काम का मूल्यांकन भी होगा

नई एचआर पॉलिसी में कर्मचारी की भूमिका केवल पदनाम तक सीमित नहीं रहेगी। हर वर्ष अप्रैल में प्रदर्शन मूल्यांकन का प्रस्ताव किया गया है। इसमें कारोबार विकास योजना की उपलब्धि, गैर-ऋण कारोबार, नियामकीय अनुपालन, लेखांकन, परिचालन दक्षता, ग्राहक और सदस्य संतुष्टि, टीमवर्क, नेतृत्व, प्रशिक्षण, नवाचार और समग्र योगदान सहित 12 प्रमुख मानदंड शामिल हैं। इसका अर्थ है कि कर्मचारी के काम को केवल लेन-देन की संख्या से नहीं, बल्कि संस्था के व्यापक विकास से जोड़कर देखा जाएगा। अच्छा प्रदर्शन करने वाले कर्मचारियों को प्रोत्साहन भी दिया जाएगा। मुनाफे में चल रही पात्र पैक्स कारोबार में पिछले वर्ष की तुलना में कम से कम 20 प्रतिशत वृद्धि होने पर अपने कर्मचारियों को अधिकतम एक माह के वेतन तक प्रोत्साहन दे सकती हैं। सक्रिय सदस्यता में वृद्धि, गैर-ऋण कारोबार, डिजिटल अनुपालन, प्रशिक्षण, लेखापरीक्षा और नवाचार के लिए भी प्रोत्साहन प्रस्तावित हैं। इससे पैक्स को सदस्य बढ़ाने, कारोबार विविध करने और डिजिटल अनुपालन मजबूत करने की प्रेरणा मिल सकती है।

कर्मचारी कल्याण और करियर की स्पष्ट सीढ़ी

एक पेशेवर एचआर नीति केवल काम और लक्ष्य तय नहीं करती, बल्कि कर्मचारी की सुरक्षा और भविष्य को भी महत्व देती है। मॉडल नीति में दुर्घटना मृत्यु, जीवन और स्वास्थ्य बीमा का प्रावधान है, जिसमें प्रीमियम कर्मचारी और संस्था के बीच साझा करने की व्यवस्था प्रस्तावित है। पांच वर्ष की निरंतर सेवा वाले कर्मचारियों के लिए ग्रेच्युटी, सेवा के दौरान मृत्यु पर परिवार के लिए एकमुश्त

सहायता, पात्र स्थायी कर्मचारियों के लिए व्यक्तिगत ऋण सुविधा और महिलाओं के लिए लागू मानकों के अनुसार मातृत्व अवकाश का प्रावधान किया गया भी है। करियर की प्रगति के लिए लिपिक या डीईओ से एई या लेखाकार, वहां से प्रबंधक और फिर सचिव तक पदोन्नति के रास्ते निर्धारित किए गए हैं। कुछ स्तरों पर पांच वर्ष और कुछ मामलों में दस वर्ष की न्यूनतम सेवा अवधि प्रस्तावित है। प्रबंधक और सचिव जैसे पदों पर आंतरिक पदोन्नति और सीधी भर्ती के बीच 50:50 अनुपात रखने की बात कही गई है। इससे कर्मचारियों को कौशल, अनुभव और प्रदर्शन के आधार पर आगे बढ़ने का स्पष्ट अवसर मिल सकता है।

ट्रेनिंग और डिजिटल एचआर पर बड़ा जोर

डिजिटल सहकारिता के दौर में नियुक्ति के बाद कर्मचारियों के लगातार प्रशिक्षण का प्रावधान प्रस्तावित पॉलिसी में किया गया है। प्रस्तावित ढांचे में पैक्स संचालन, सहकारी सिद्धांत, लेखांकन, व्यवसाय विकास योजना, ई-पैक्स या ईआरपी, वित्तीय अनुपालन, लेखापरीक्षा, ग्राहक सेवा, शासन, जोखिम प्रबंधन, कृषि और गैर-ऋण व्यवसाय मॉडल, नेतृत्व, डिजिटल भुगतान, साइबर सुरक्षा और डेटा गोपनीयता जैसे विषय शामिल हैं। डिजिटल भुगतान, साइबर सुरक्षा और डेटा गोपनीयता को वार्षिक प्रशिक्षण से जोड़ने का प्रस्ताव है। एचआर व्यवस्था भी डिजिटल होगी। नाबार्ड के समन्वय से केंद्रीकृत ह्यूमेन रिसोर्सेज इन्फॉर्मेशन सिस्टम यानी एचआरआईएस विकसित करने का प्रस्ताव है, जिसे ई-पैक्स के एचआरएमएस मॉड्यूल और कंप्यूटरीकरण परियोजना से जोड़ा जाएगा। कर्मचारी रिकॉर्ड, रिक्तियां, प्रदर्शन, भर्ती, प्रशिक्षण और स्थानांतरण जैसी जानकारी डिजिटल रूप से उपलब्ध होगी। इससे यह पता लगाना आसान होगा कि कहां कर्मचारी कम हैं, कहां प्रशिक्षण की जरूरत है और किन संस्थाओं को अतिरिक्त सहायता चाहिए।

कमजोर पैक्स को सहारा, लक्ष्य आत्मनिर्भरता

प्रस्तावित नीति उन पैक्स के लिए आगे बढ़ने का रास्ता खोलती है जिनमें क्षमता और सदस्य आधार है, लेकिन वे फिलहाल वित्तीय दबाव या नुकसान में हैं। इसके लिए जिला स्तरीय पैक्स सहायता निधि यानी डीएलपीएएफ का प्रस्ताव है। पैक्स को मिलने वाली सहायता जरूरत आधारित होगी और धीरे-धीरे कम होती जाएगी। वित्तीय दबाव में चल रही जिन पैक्स को इस फंड से सहायता दी जाएगी उन्हें पहले वर्ष 100 प्रतिशत, दूसरे वर्ष 80 प्रतिशत, तीसरे वर्ष 60 प्रतिशत, चौथे वर्ष 40 प्रतिशत और पांचवें वर्ष 20 प्रतिशत तक सहायता दी जाएगी। सहायता प्राप्त करने के लिए संबंधित पैक्स को ऋण और गैर-ऋण कारोबार बढ़ाने वाली व्यवसाय विकास योजना प्रस्तुत करनी होगी। इसका लक्ष्य तीसरे वर्ष तक परिचालन मुनाफा हासिल करना और पांचवें वर्ष तक पूर्ण वित्तीय स्थिरता हासिल करना है। यानी सहायता स्थायी सब्सिडी नहीं, बल्कि सुधार के लिए समय और संसाधन देकर आत्मनिर्भरता की ओर ले जाने का माध्यम होगी।■

सहकार से समृद्धि का नया अध्याय

मॉडल एचआर नीति का व्यापक संदेश यह है कि सहकारिता को मजबूत करने के लिए केवल पूंजी, तकनीक या बुनियादी ढांचा पर्याप्त नहीं है। सही व्यक्ति, सही कौशल, स्पष्ट जिम्मेदारी और सही प्रोत्साहन व्यवस्था भी उतनी ही जरूरी है। पैक्स की ताकत उसकी ग्रामीण पहुंच और सदस्य आधारित संरचना है, लेकिन इस ताकत को आधुनिक आर्थिक अवसरों में बदलने के लिए पेशेवर प्रबंधन आवश्यक है। यदि यह ढांचा स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप पारदर्शी और प्रभावी तरीके से लागू होता है तो इसका असर पैक्स के भीतर से बाहर तक दिखाई दे सकता है। बेहतर प्रशिक्षित कर्मचारी किसानों और सदस्यों को बेहतर सेवा दे सकते हैं, डिजिटल रिकॉर्ड पारदर्शिता बढ़ा सकता है, प्रदर्शन आधारित प्रोत्साहन कारोबार विस्तार को गति दे सकता है और सहायता निधि कमजोर लेकिन संभावनाशील समितियों को आत्मनिर्भर बनने का अवसर दे सकती है।

पैक्स बनेंगे वन स्टॉप शॉप

एक ही स्थान पर सरकार की विभिन्न योजनाओं, सेवाओं और सुविधाओं को उपलब्ध कराने वाले ग्रामीण केंद्रों में बदलने की तैयारी कर रहा सहकारिता मंत्रालय

चुनी गई सेवाओं का उपयुक्त पैक्स और संबंधित भौगोलिक क्षेत्रों के साथ मिलान किया जाएगा और इन्हें पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लागू किया जाएगा

युवा सहकार टीम

केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय ने एक महत्वपूर्ण पहल में देश की प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पैक्स) की भूमिका को नए सिरे से परिभाषित करने की दिशा में कदम बढ़ाया है। अभी तक गांवों में पैक्स की पहचान मुख्य रूप से किसानों को ऋण और कृषि से जुड़ी वित्तीय सुविधाएं उपलब्ध कराने वाली सहकारी संस्था के रूप में रही है, लेकिन आने वाले समय में इन्हें 'वन स्टॉप शॉप' यानी एक ही स्थान पर अनेक सेवाएं उपलब्ध कराने वाले ग्रामीण केंद्रों मंस बदलने की तैयारी है।

सहकारिता मंत्रालय के सचिव डॉ. आशीष भूटानी ने इस पहल को आगे बढ़ाने के लिए अंतर-मंत्रालयी बैठक की। बैठक का उद्देश्य अलग-अलग मंत्रालयों और विभागों की योजनाओं, सेवाओं और सुविधाओं को पैक्स के विशाल ग्रामीण नेटवर्क के माध्यम से आम लोगों और किसानों तक पहुंचाने की संभावनाओं को तलाशना था। इस पहल के पीछे सोच सरल लेकिन दूरगामी है, गांव के व्यक्ति को अलग-अलग सरकारी दफ्तरों और एजेंसियों के चक्कर लगाने की बजाय अधिक से अधिक सेवाएं अपने गांव या आसपास की पैक्स में ही उपलब्ध हों।

पैक्स देश की सहकारी व्यवस्था की सबसे निचली और गांव के सबसे करीब मौजूद संस्थाओं में शामिल हैं। इनका पारंपरिक काम किसानों को अल्पकालीन कृषि ऋण जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराना रहा है। अब सरकार चाहती है कि पैक्स केवल ऋण देने वाली संस्था न रहें। उन्हें ऐसी स्थानीय आर्थिक और सेवा इकाई के रूप में विकसित किया जाए जहां किसान और ग्रामीण नागरिक सरकारी योजनाओं, उत्पादों, प्रशिक्षण, बाजार से जुड़ी सुविधाओं और विभिन्न सेवाओं तक

पहुंच हासिल कर सकें। यदि यह मॉडल सफल होता है तो पैक्स का स्वरूप काफी बदल सकता है। गांव में स्थित एक सहकारी संस्था केवल किसान को कर्ज देने के बजाय उसे कृषि से जुड़े उत्पाद, प्रशिक्षण, सरकारी योजनाओं की जानकारी, बाजार से संपर्क और दूसरी आवश्यक सेवाएं भी उपलब्ध करा सकती है।इससे पैक्स के लिए भी कारोबार और आय के नए रास्ते खुलने की संभावना है।

बैठक में शामिल विभागों से कहा गया है कि वे ऐसी योजनाओं और सेवाओं की पहचान करें जिन्हें पैक्स के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में उपलब्ध कराया जा सकता है। इसके बाद चुनी गई सेवाओं का उपयुक्त पैक्स और संबंधित भौगोलिक क्षेत्रों के साथ मिलान किया जाएगा। पहले इन्हें पायलट परियोजनाओं के रूप में लागू किया जाएगा। पायलट परियोजनाओं का महत्व इसलिए है क्योंकि हर सेवा हर इलाके में एक जैसी जरूरत नहीं रखती। किसी क्षेत्र में कृषि से जुड़ी सुविधा अधिक उपयोगी हो सकती है, तो कहीं पशुपालन, मत्स्य पालन, खाद्य प्रसंस्करण या ग्रामीण विकास से जुड़ी सेवा की ज्यादा जरूरत हो सकती है। पायलट परियोजनाओं से यह समझने में मदद मिलेगी कि किस प्रकार की पैक्स में कौन-सी सेवाएं सफलतापूर्वक चलाई जा सकती हैं और उसके लिए मानव संसाधन, तकनीक तथा बुनियादी ढांचे की कितनी आवश्यकता होगी। सफल परिणाम मिलने पर इस मॉडल को देश के दूसरे हिस्सों में भी विस्तार दिया जा सकता है।

वन स्टॉप शॉप की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता इसका बहु-विभागीय स्वरूप है। प्रस्तावित व्यवस्था में खाद्य वितरण, खाद्य प्रसंस्करण, कृषि एवं किसान कल्याण, उर्वरक, पंचायती राज, उपभोक्ता मामले, कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा, ग्रामीण विकास, मत्स्य पालन, पशुपालन और भूमि संसाधन जैसे कई क्षेत्रों की योजनाओं तथा सेवाओं को पैक्स के माध्यम से जोड़ने की संभावनाओं पर विचार किया जा रहा है। इसका अर्थ यह है कि भविष्य की पैक्स केवल सहकारिता विभाग की एक इकाई बनकर सीमित नहीं रहेगी। वह अलग-अलग मंत्रालयों की योजनाओं और ग्रामीण नागरिकों के बीच लास्ट-माइल डिलीवरी प्लेटफॉर्म की भूमिका निभा सकती है। सरकारी योजनाएं अक्सर राष्ट्रीय या राज्य स्तर पर तैयार होती हैं, लेकिन उनकी वास्तविक सफलता तब होती है जब सुविधा अंतिम लाभार्थी तक आसानी से पहुंचे। गांव में पहले से मौजूद पैक्स का नेटवर्क इस दूरी को कम करने में उपयोगी साबित हो सकता है।

कल्पना कीजिए कि किसी किसान को खेती के लिए ऋण चाहिए। अभी वह पैक्स जाता है। लेकिन उसी किसान को किसी दूसरी सरकारी योजना की जानकारी चाहिए, प्रशिक्षण लेना है, बाजार से जुड़ना है या कृषि से संबंधित कोई और सेवा प्राप्त करनी है तो उसे दूसरी संस्था या कार्यालय तक जाना पड़ सकता है। यदि अलग-अलग सेवाएं पैक्स से जुड़ती हैं तो किसान को कई जरूरतों के लिए एक ही स्थानीय केंद्र पर सहायता मिल सकती है। इससे समय और आवाजाही दोनों कम हो सकते हैं। साथ ही गांव की सहकारी संस्था का किसान के साथ संबंध केवल ऋणदाता का न रहकर समग्र आर्थिक सहयोगी का हो सकता है। इस पहल का दूसरा महत्वपूर्ण पहलू पैक्स की अपनी आर्थिक स्थिति है। कोई भी सहकारी संस्था तभी मजबूत हो सकती है जब उसके पास नियमित कारोबारी गतिविधियां और टिकाऊ आय के स्रोत हों। यदि पैक्स केवल सीमित ऋण कारोबार पर निर्भर रहती है तो उसकी संभावनाएं भी सीमित रहती हैं।

वन स्टॉप शॉप की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता इसका बहु-विभागीय स्वरूप है। प्रस्तावित व्यवस्था में खाद्य वितरण, खाद्य प्रसंस्करण, कृषि एवं किसान कल्याण, उर्वरक, पंचायती राज, उपभोक्ता मामले, कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा, ग्रामीण विकास, मत्स्य पालन, पशुपालन और भूमि संसाधन जैसे कई क्षेत्रों की योजनाओं तथा सेवाओं को पैक्स के माध्यम से जोड़ने की संभावनाओं पर विचार किया जा रहा है।

वन स्टॉप शॉप के माध्यम से विभिन्न सेवाओं और कारोबारी गतिविधियों के जुड़ने से पैक्स को नई भूमिका मिल सकती है। सरकारी सेवाओं की डिलीवरी, विभिन्न उत्पादों की उपलब्धता, प्रशिक्षण, बाजार संपर्क और दूसरी आर्थिक गतिविधियां पैक्स को बहुउद्देशीय ग्रामीण व्यवसाय केंद्र बनाने में मदद कर सकती हैं। इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सहकारी संस्थाओं की प्रासंगिकता भी बढ़ेगी।■

एग्रीकल्चर छात्रों को अब सीधे खाते में मिलेगी स्कॉलरशिप

केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल का किया शुभारंभ

युवा सहकार टीम

कृषि शिक्षा को अधिक मजबूत, आधुनिक और विद्यार्थियों के लिए सुविधाजनक बनाने की दिशा में केंद्र सरकार ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एग्रीकल्चर की पढ़ाई कर रहे विद्यार्थियों के लिए नई छात्रवृत्ति व्यवस्था की शुरुआत की है। इसके तहत देशभर के 6,000 से अधिक विद्यार्थियों को 21.35 करोड़ रुपये की छात्रवृत्ति सीधे उनके बैंक खातों में भेजी गई। यह राशि राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल के माध्यम से डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से भेजी गई है। शिवराज सिंह ने इस पोर्टल का भी शुभारंभ किया।

इस नई व्यवस्था की शुरुआत नई दिल्ली स्थिति आईसीएआर-आईएआरआई, पूसा में आयोजित कार्यक्रम के दौरान की गई। इसका उद्देश्य एग्रीकल्चर के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति मिलने की प्रक्रिया को तेज, पारदर्शी और सरल बनाना है। अब पात्र विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति की राशि हर महीने सीधे उनके बैंक खातों में मिलेगी। इससे भुगतान में होने वाली देरी कम होगी और विद्यार्थियों को बार-बार कार्यालयों या संस्थानों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। कार्यक्रम में कृषि विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि छात्रवृत्ति को केवल आर्थिक सहायता के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। यह कृषि शिक्षा को मजबूत बनाने और युवाओं के लिए बेहतर अवसर पैदा करने का माध्यम भी है। समय पर आर्थिक सहयोग मिलने से विद्यार्थी अपनी पढ़ाई, शोध और कौशल विकास पर अधिक ध्यान दे सकेंगे।

कृषि मंत्री ने विशेष रूप से व्यावहारिक कृषि शिक्षा पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि केवल कक्षा में पढ़ाई करने से अच्छे किसान, कृषि वैज्ञानिक या कृषि उद्यमी तैयार नहीं किए जा सकते। विद्यार्थियों को खेतों, किसानों और वास्तविक कृषि परिस्थितियों से जोड़ना आवश्यक है। व्यावहारिक प्रशिक्षण के माध्यम से छात्र खेती की समस्याओं को बेहतर ढंग से समझ सकेंगे और उनके लिए नए समाधान विकसित कर पाएंगे। उन्होंने युवाओं से पारंपरिक नौकरी की सोच से आगे बढ़कर कृषि स्टार्टअप, नवाचार, अनुसंधान और उद्यमिता के क्षेत्र में आगे आने की अपील की। कृषि शिक्षा को आधुनिक तकनीक, उद्योग की जरूरतों और व्यावहारिक प्रशिक्षण से जोड़ने पर आने वाले समय में रोजगार के साथ-साथ नए कृषि व्यवसाय भी विकसित किए जा सकते हैं।

इस पहल का लाभ केवल छात्रों तक सीमित नहीं रहेगा। बेहतर प्रशिक्षित कृषि स्नातक आगे चलकर किसानों, किसान उत्पादक संगठनों, ग्रामीण उद्यमों, कृषि स्टार्टअप और कृषि से जुड़े संस्थानों को भी मजबूत कर सकते हैं। हांलाकि इस घोषणा में सहकारी समितियों का सीधे उल्लेख नहीं किया गया है, लेकिन कृषि शिक्षा, उद्यमिता और किसानों की आय बढ़ाने पर जोर दिए जाने से भविष्य में कृषि सहकारी संस्थाओं और ग्रामीण संगठनों को भी अप्रत्यक्ष लाभ मिल सकता है।

यह नई छात्रवृत्ति व्यवस्था कृषि विद्यार्थियों को आर्थिक सुरक्षा देने के साथ उन्हें तकनीक, शोध, नवाचार और उद्यमिता से जोड़ने का प्रयास है। यदि कृषि शिक्षा को खेत की वास्तविक जरूरतों से जोड़ा जाता है, तो आज के विद्यार्थी भविष्य में किसानों की आय बढ़ाने, कृषि को आधुनिक बनाने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।■

डिजिटल सहकारिता: गांव की चौपाल से डिजिटल प्लेटफॉर्म तक

युवा सहकार टीम

भारत में सहकारिता की जड़ें गांव-गांव तक फैली हुई हैं। किसानों को फसल ऋण चाहिए, खाद-बीज लेना हो, अपनी उपज से जुड़ी कोई सेवा प्राप्त करनी हो या गांव में आर्थिक गतिविधियों को सामूहिक रूप से आगे बढ़ाना हो, सहकारी संस्थाएं लंबे समय से उसकी सबसे नजदीकी संस्थागत कड़ी रही हैं। मगर समय के साथ सहकारिता के सामने भी बड़ी चुनौती खड़ी हुई- पुराने कागजी रिकॉर्ड, खातों के रख-रखाव में लगने वाला समय, अलग-अलग प्रणालियां और सेवाओं में देरी।

अब यही तस्वीर तेजी से बदल रही है। पैक्स के कंप्यूटरीकरण के बाद से डिजिटल सिस्टम ने सहकारी संस्थाओं को परंपरागत बही-खातों से निकालकर आधुनिक, पारदर्शी और तकनीक आधारित व्यवस्था की ओर बढ़ाया है। गांव की प्राथमिक कृषि साख समिति (पैक्स) में जो काम कभी रजिस्टर और फाइलों के सहारे होता था, वह अब एक साझा डिजिटल प्रणाली पर आने लगा है। इसका सबसे बड़ा लाभ उस किसान और सदस्य को मिल रहा है, जिसके लिए सहकारिता का अर्थ केवल एक संस्था नहीं, बल्कि रोजमर्रा की आर्थिक जरूरतों का भरोसेमंद माध्यम है।

देशभर में 63,686 पैक्स को ईआरपी आधारित राष्ट्रीय सॉफ्टवेयर पर किया जा चुका है ऑनबोर्ड

पैक्स के डिजिटल होने से ऋण संबंधी प्रक्रिया को तेज और व्यवस्थित बनाने, लेन-देन की लागत कम करने तथा जिला केंद्रीय सहकारी बैंक और राज्य सहकारी बैंक के साथ खातों के बेहतर मिलान का रास्ता तैयार हुआ है। सहकारिता मंत्रालय के अनुसार, कंप्यूटरीकरण का उद्देश्य विशेष रूप से छोटे और सीमांत किसानों के लिए सेवा वितरण को मजबूत करना, पारदर्शिता बढ़ाना और संस्थाओं के प्रति भरोसा मजबूत करना है।

डिजिटल सहकारिता का सबसे बड़ा लाभ शायद किसी एक आंकड़े में नहीं मापा जा सकता। इसका असली असर तीन स्तरों पर दिखाई देता है– समय की बचत, व्यवस्था में पारदर्शिता और सदस्य के विश्वास में वृद्धि। जब ऋण का रिकॉर्ड स्पष्ट हो, खातों की जानकारी व्यवस्थित मिले, ऑडिट समय पर हो, वित्तीय रिपोर्ट डिजिटल रूप से तैयार हो और संस्था दूसरी सरकारी सेवाओं से जुड़ सके, तो सहकारी व्यवस्था अधिक मजबूत होती है।

सहकारी समितियों में दशकों से खाते, ऋण संबंधी विवरण, सदस्यता रिकॉर्ड और लेन-देन की जानकारी बड़ी-बड़ी पंजियों में दर्ज की जाती रही। पुराने रिकॉर्ड तलाशने, खातों का मिलान करने और रिपोर्ट तैयार करने में समय लगता था। मानवीय त्रुटियों की आशंका भी बनी रहती थी। पैक्स के कंप्यूटरीकरण ने इस व्यवस्था में बड़ा बदलाव शुरू किया है। केंद्र सरकार ने कार्यशील पैक्स को एक समान इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग (ईआरपी) आधारित राष्ट्रीय सॉफ्टवेयर पर लाने की परियोजना शुरू की। शुरुआत में लगभग 63 हजार पैक्स को शामिल करने का लक्ष्य था, जिसे बाद में बढ़ाकर 79,630 पैक्स कर दिया गया। इस परियोजना का कुल वित्तीय परिव्यय बढ़कर 2,925.39 करोड़ रुपये हो चुका है। 29 जुलाई, 2026 तक देशभर में 63,686 पैक्स को ईआरपी आधारित राष्ट्रीय सॉफ्टवेयर पर ऑनबोर्ड किया जा चुका था। ये आंकड़े केवल कंप्यूटर लगाने की कहानी नहीं बताते। इनके पीछे सहकारिता के काम करने के तरीके में एक बुनियादी परिवर्तन दिखाई देता है। रिकॉर्ड डिजिटल हो रहे हैं, वित्तीय विवरण एक तय प्रारूप में बन रहे हैं और प्रबंधन से लेकर ऑडिट तक की प्रक्रिया अधिक व्यवस्थित हो रही है।

किसानों के लिए क्या बदला?

डिजिटल सहकारिता का वास्तविक अर्थ तभी है जब उसका लाभ आखिरी सदस्य तक पहुंचे। पैक्स के डिजिटल होने से ऋण संबंधी प्रक्रिया को तेज और व्यवस्थित बनाने, लेन-देन की लागत कम करने तथा जिला केंद्रीय सहकारी बैंक और राज्य सहकारी बैंक के साथ खातों के बेहतर मिलान का रास्ता तैयार हुआ है। सहकारिता मंत्रालय के अनुसार, कंप्यूटरीकरण का उद्देश्य विशेष रूप से छोटे और सीमांत किसानों के लिए सेवा वितरण को मजबूत करना, पारदर्शिता बढ़ाना और संस्थाओं के प्रति भरोसा मजबूत करना है।

इस बदलाव को गांव के एक किसान के अनुभव से समझा जा सकता है। पहले किसी सदस्य को अपने पुराने ऋण, जमा राशि या खाते की जानकारी के लिए कई रजिस्टर देखने पड़ सकते थे। कर्मचारी को भी रिकॉर्ड तलाशने और मिलान करने में समय लगता था। डिजिटल प्रणाली में वही जानकारी व्यवस्थित रूप से उपलब्ध होने से प्रक्रिया सरल और तेज हो गई है। यानी डिजिटल सहकारिता का लाभ केवल कार्यालय में बैठे कर्मचारी तक सीमित नहीं है। इसका असर किसान के समय, उसकी सुविधा और संस्था के प्रति उसके विश्वास पर भी पड़ता है।

पारदर्शिता बनी सबसे बड़ी ताकत

सहकारी संस्था की सफलता का सबसे मजबूत आधार होता है सदस्यों का विश्वास। और विश्वास वहीं मजबूत होता है जहां हिसाब स्पष्ट हो। ईआरपी आधारित प्रणाली में लेखांकन, वित्तीय विवरण, प्रबंधन सूचना प्रणाली और ऑडिट से जुड़ी जानकारियां डिजिटल रूप में उपलब्ध होती हैं। इससे लेन-देन का रिकॉर्ड तैयार होता है और ऑडिट ट्रेल के माध्यम से यह पता लगाना आसान होता है कि कोई वित्तीय प्रविष्टि कब और किस प्रक्रिया से हुई। सरकार के अनुसार साझा राष्ट्रीय सॉफ्टवेयर में अकाउंटिंग, वैधानिक ऑडिट और मैनेजमेंट इन्फार्मेशन सिस्टम के मानकीकृत मॉड्यूल शामिल हैं। डिजिटल रिकॉर्ड और मानकीकृत वित्तीय रिपोर्टिंग से पैक्स की जवाबदेही और पारदर्शिता मजबूत करने में मदद मिल रही है। यह बदलाव इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि सहकारी संस्था में पूंजी और गतिविधियां

सदस्यों से जुड़ी होती हैं। जब सदस्य के सामने लेन-देन और संस्था की आर्थिक स्थिति अधिक स्पष्ट होती है, तो उसकी भागीदारी और भरोसा दोनों बढ़ते हैं।

ऑडिट हुआ आसान, निगरानी हुई प्रभावी

डिजिटलीकरण का बड़ा लाभ ऑडिट में भी दिखाई देता है। पहले अलग-अलग फाइलों से जानकारी जुटाना पड़ता था। अब डिजिटल रिकॉर्ड उपलब्ध होने से ऑडिट के लिए जरूरी सूचनाओं को व्यवस्थित रूप में देखा जा सकता है। दिसंबर 2025 तक उपलब्ध सरकारी आंकड़ों के अनुसार 38,982 पैक्स में ऑन-सिस्टम ऑडिट सफलतापूर्वक पूरा किया जा चुका था, जबकि 60 हजार से अधिक पैक्स, ईपैक्स सॉफ्टवेयर से जुड़ चुके थे। इससे पता चलता है कि डिजिटलीकरण केवल डेटा एंट्री तक सीमित नहीं है, बल्कि वित्तीय अनुशासन और संस्थागत निगरानी को भी नई दिशा दे रहा है।

तकनीक से बढ़ता भरोसा

डिजिटल सहकारिता का सबसे बड़ा लाभ शायद किसी एक आंकड़े में नहीं मापा जा सकता। इसका असली असर तीन स्तरों पर दिखाई देता है- समय की बचत, व्यवस्था में पारदर्शिता और सदस्य के विश्वास में वृद्धि। जब ऋण का रिकॉर्ड स्पष्ट हो, खातों की जानकारी व्यवस्थित मिले, ऑडिट समय पर हो, वित्तीय रिपोर्ट डिजिटल रूप से तैयार हो और संस्था दूसरी सरकारी सेवाओं से जुड़ सके, तो सहकारी व्यवस्था अधिक मजबूत होती है। इसके साथ कर्मचारियों के लिए भी काम आसान होता है। बार-बार एक ही जानकारी अलग-अलग रजिस्टरों में दर्ज करने की आवश्यकता कम हो सकती है। प्रबंधन को संस्था की स्थिति समझने के लिए बेहतर डेटा मिलता है और निर्णय अधिक तथ्य आधारित हो सकते हैं।

आगे की राह

डिजिटल सहकारिता की यात्रा अभी जारी है। कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर उपलब्ध करा देना पहला चरण है। इसका पूरा लाभ तभी मिलेगा जब समिति के कर्मचारी प्रशिक्षित हों, इंटरनेट और तकनीकी सहायता नियमित मिले, डेटा समय पर अपडेट हो और सदस्यों को भी डिजिटल सेवाओं के इस्तेमाल की जानकारी दी जाए। साइबर सुरक्षा और डेटा की गोपनीयता पर भी उतना ही ध्यान देना होगा। तकनीक जितनी सुविधा देती है, उसके सुरक्षित और जिम्मेदार उपयोग की आवश्यकता भी उतनी ही बढ़ जाती है। फिर भी बदलाव की दिशा स्पष्ट है। कभी गांव की सहकारी समिति की पहचान लकड़ी की अलमारी में रखी बही और मोटे रजिस्टरों से होती थी। आज उसी समिति में कंप्यूटर स्क्रीन पर सदस्य का खाता खुल रहा है, वित्तीय रिपोर्ट तैयार हो रही है और डिजिटल नेटवर्क उसे जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर की व्यवस्थाओं से जोड़ रहा है।■

एक समिति, कई सेवाएं

डिजिटल सहकारिता का अगला चरण पैक्स को केवल ऋण देने वाली संस्था की बजाय बहु-सेवा केंद्र के रूप में विकसित करने से जुड़ा है। पैक्स को किसान सेवाओं, उर्वरक और बीज वितरण, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, कॉमन सर्विस सेंटर, जन औषधि केंद्र, पेट्रोल पंप खोलने और एलपीजी डिस्ट्रिब्यूटरशिप जैसी अनेक गतिविधियों से जोड़ने की दिशा में काम किया जा रहा है। ईआरपी सॉफ्टवेयर को नेशनल कोऑपरेटिव डाटाबेस तथा अन्य सरकारी डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़ने की प्रक्रिया भी आगे बढ़ी है। इसका अर्थ यह है कि भविष्य की सहकारी समिति केवल खाते और ऋण संभालने वाली संस्था नहीं, बल्कि ग्रामीण नागरिक को उसके गांव के पास अनेक सेवाएं उपलब्ध कराने वाला डिजिटल केंद्र बन सकती है।

डिजिटल परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा नेशनल कोऑपरेटिव डाटाबेस भी है। पहले देश में कितनी सहकारी समितियां हैं, वे किन क्षेत्रों में काम करती हैं और उनकी आर्थिक स्थिति क्या है- इन जानकारियों को एकीकृत रूप में प्राप्त करना आसान नहीं था। अब नेशनल कोऑपरेटिव डाटाबेस में देश की लाखों सहकारी संस्थाओं का विवरण एक स्थान पर उपलब्ध है। 15 जुलाई, 2026 तक देश में 8,53,430 सहकारी समितियां दर्ज थीं, जिनमें लगभग 6.63 लाख कार्यशील हैं। डेटाबेस में समितियों की लोकेशन, सदस्यता, आर्थिक गतिविधियां, बुनियादी ढांचा, वित्तीय प्रदर्शन और ऑडिट जैसी जानकारियां शामिल की गई हैं। इसका फायदा नीति निर्माण में भी है। सरकार यह पहचान सकती है कि किन क्षेत्रों में सहकारी संस्थाओं की पहुंच कम है, कहां नई संस्था की आवश्यकता है और किन समितियों को मजबूत किए जाने की जरूरत है।

डिजिटलीकरण का बड़ा लाभ ऑडिट में भी दिखाई देता है। पहले अलग-अलग फाइलों से जानकारी जुटाना पड़ता था। अब डिजिटल रिकॉर्ड उपलब्ध होने से ऑडिट के लिए जरूरी सूचनाओं को व्यवस्थित रूप में देखा जा सकता है।

टीएसयू में शुरू हुए नए कोर्स

पैक्स, फिशरीज, डेयरी, कोऑपरेटिव बैंकिंग और साइबर सुरक्षा के लिए सर्टिफिकेट कोर्स की हुई शुरुआत

युवा सहकार टीम

सहकारी शिक्षा को नई पहचान और धार देने के लिए पिछले साल ही देश में पहली बार त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी (टीएसयू) की स्थापना की गई। इस यूनिवर्सिटी के पहले सत्र (2025-26) का बैच पढ़ाई पूरी कर कैंपस प्लेसमेंट पा चुका है। सहकारिता क्षेत्र को आधुनिक प्रबंधन, वित्त और तकनीक से जोड़ने की दिशा में त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय ने महत्वपूर्ण पहल की है। शैक्षणिक वर्ष 2025-26 में टीएसयू ने तीन एमबीए कोर्स शुरू किए थे। वर्ष 2026-27 में यूनिवर्सिटी ने पांच विशेष सर्टिफिकेट कोर्स शुरू किए हैं। इन पाठ्यक्रमों का उद्देश्य सहकारी संस्थाओं के प्रबंधन को अधिक पेशेवर बनाना, उनसे जुड़े कर्मचारियों तथा पदाधिकारियों की कार्यकुशलता बढ़ाना है।

टीएसयू ने पिछले सत्र में जिन तीन नए एमबीए कोर्स की शुरुआत की थी, उनमें कोऑपरेटिव मैनेजमेंट में एमबीए, कोऑपरेटिव बैंकिंग एवं फाइनेंस में मैनेजमेंट और एग्रीबिजनेस मैनेजमेंट शामिल हैं। इन कोर्सेज के माध्यम से स्टूडेंट्स को कोऑपरेटिव सोसायटीज के संचालन, वित्तीय प्रबंधन, बैंकिंग व्यवस्था और कृषि व्यवसाय की आधुनिक जरूरतों के अनुरूप तैयार किया जा रहा है।

सहकारी क्षेत्र के विस्तार के साथ अब ऐसे पेशेवरों की मांग भी बढ़ रही है, जो परंपरागत

सहकारिता की समझ के साथ आधुनिक बिजनेस मैनेजमेंट और वित्तीय प्रणाली में भी दक्ष हों। इसी जरूरत को देखते हुए विश्वविद्यालय ने एमबीए कार्यक्रमों के साथ जमीनी स्तर पर काम करने वाले कर्मचारियों के लिए भी विशेष प्रशिक्षण पाठ्यक्रम तैयार किए हैं। वर्ष 2026-27 के दौरान शुरू हुए पांच सर्टिफिकेट कोर्स में पहला है पैक्स के सचिवों और कर्मचारियों के लिए बिजनेस मैनेजमेंट और गवर्नेंस में सर्टिफिकेट कोर्स। इसका उद्देश्य पैक्स के रोजमर्रा के संचालन, वित्तीय अनुशासन और प्रशासनिक व्यवस्था को बेहतर बनाना है।

दूसरा पाठ्यक्रम प्राथमिक मत्स्य सहकारी समितियों के सचिवों और कर्मचारियों के लिए बिजनेस मैनेजमेंट और गवर्नेंस में सर्टिफिकेट कोर्स है। इसके माध्यम से मत्स्य सहकारी समितियों से जुड़े कर्मियों को व्यवसाय संचालन और संस्थागत प्रबंधन की व्यावहारिक जानकारी दी जाएगी। तीसरा है डेयरी सहकारी समितियों के सचिवों और कर्मचारियों के लिए बिजनेस मैनेजमेंट और गवर्नेंस में सर्टिफिकेट कोर्स। डेयरी सहकारिता ग्रामीण अर्थव्यवस्था और किसानों की आय से सीधे जुड़ी है, इसलिए बेहतर प्रबंधन से इन समितियों के कामकाज को अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है।

विश्वविद्यालय ने जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों यानी डीसीसीबी के लिए भी विशेष पहल की है। जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों के निदेशक मंडल के लिए नेतृत्व विकास में प्रमाण-पत्र पाठ्यक्रम के जरिये बैंकिंग संस्थाओं में निर्णय क्षमता, नेतृत्व और बेहतर प्रशासन को मजबूत करने पर जोर रहेगा। वहीं डिजिटल बैंकिंग के बढ़ते दायरे को देखते हुए सहकारी बैंकों के लिए साइबर सुरक्षा में प्रमाण-पत्र पाठ्यक्रम भी तैयार किया गया है। यह कोर्स साइबर खतरों, डिजिटल धोखाधड़ी और डेटा सुरक्षा जैसी चुनौतियों से निपटने में सहकारी बैंकों की क्षमता बढ़ाने में मदद करेगा।

टीएसयू के नए पाठ्यक्रम केवल डिग्री देने तक सीमित नहीं हैं। एमबीए से लेकर पैक्स, मत्स्य, डेयरी, डीसीसीबी और सहकारी बैंकों के लिए विशेष प्रशिक्षण तक विश्वविद्यालय की यह पहल सहकारिता क्षेत्र को अधिक पेशेवर, तकनीकी रूप से सक्षम और भविष्य की जरूरतों के अनुरूप बनाने की दिशा में अहम कदम साबित होगी।■

वर्ष 2026-27 के दौरान शुरू हुए पांच सर्टिफिकेट कोर्स में पहला है पैक्स के सचिवों और कर्मचारियों के लिए बिजनेस मैनेजमेंट और गवर्नेंस में सर्टिफिकेट कोर्स। इसका उद्देश्य पैक्स के रोजमर्रा के संचालन, वित्तीय अनुशासन और प्रशासनिक व्यवस्था को बेहतर बनाना है।

एशियाड में स्वर्ण जीत ओलंपिक के लिए क्वॉलिफाई करना अगला लक्ष्य: सविता

भारतीय महिला हॉकी टीम में इस समय सबसे अनुभवी और उम्रदराज ओलंपियन हैं गोलरक्षक 36 बरस की सविता। 2018 में जकार्ता में एशियाई खेलों में रजत, 2014 में इंचियोन एवं 2022 में हांगजू में एशियाई खेलों में कांसा जीतने तथा 2020 में टोक्यो ओलंपिक में चौथे और एम्सतलवीन (नीदरलैंड) में जर्मनी जैसी मजबूत टीम को 3–1 से हरा कर 16वें एफआईएच महिला हॉकी विश्व कप में पांचवें स्थान पर रही भारतीय टीम की वह अहम गोलरक्षक रहीं। सविता कुल तीन महिला हॉकी विश्व कप, दो ओलंपिक खेलों (2016 में रियो और 2020 में टोक्यो) में भारत के किले की बतौर गोलरक्षक प्रहरी रही। वह भारत की तीन महिला एशियन चैंपियंस ट्रॉफी (2016 में सिंगापुर, 2023 में रांची और 2024 में राजगीर) में स्वर्ण जीतने वाली टीम की अहम सदस्य रहीं।

सविता का जन्म हरियाणा के सिरसा जिले के जोडखा गांव में 11 जुलाई, 1990 को हुआ। उनकी शादी सोनीपत के सॉफ्टवेयर इंजिनियर और म्यूजिक कंपोजर अंकित बलहारा से हुई, जो कनाडा में रहते हैं। उन्हें हॉकी खेलने के लिए उनके दादा रंजीत सिंह पूनिया ने प्रेरित किया। बेशक सविता अभी भी बतौर गोलरक्षक भारत के किले की सबसे मजबूत प्रहरी हैं, मगर वह इस हकीकत से वाकिफ हैं कि उनके अंतर्राष्ट्रीय हॉकी करियर की सांझ धीरे से ही, पर अब दस्तक देने लगी है। वह कब तक भारत के लिए खेलेंगी (2026 के एशियाई खेलों या फिर 2028 के लॉस एंजेल्स ओलंपिक तक) अभी इस बाबत कुछ भी साफ साफ तय नहीं कर पाई हैं। बावजूद इसके सविता ने इतना जरूर साफ किया कि एम्सतलवीन (नीदरलैंड) में महिला हॉकी विश्व कप में बेहद करीब से सेमीफाइनल में पहुंचने से चूकने के बाद अब भारतीय टीम अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर इसी महीने एशियाई खेलों में स्वर्ण जीतने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। 318 अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच खेल चुकी **सविता** से वेगनर स्टेडियम, एम्सतलवीन (नीदरलैंड) में वरिष्ठ पत्रकार **सत्येन्द्र पाल सिंह** की उनसे हुई खास बातचीत के प्रमुख अंश:

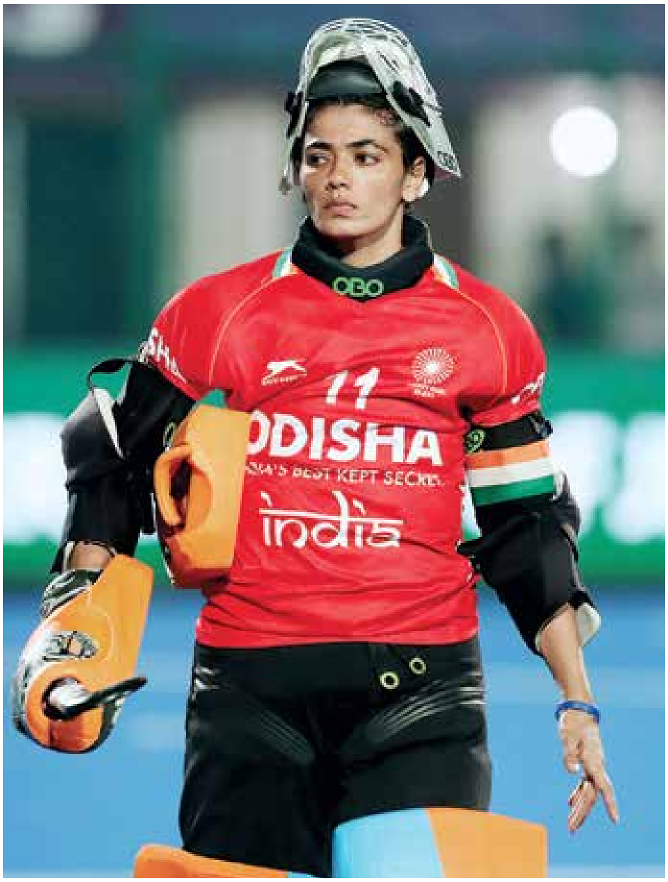

सभी सीनियर खिलाड़ियों के मार्गदर्शन और सलीमा टेटे की अगुआई में भारत के एम्सतलवीन में 2026 महिला हॉकी विश्व कप में प्रदर्शन को आप कैसे आंकती हैं?

हमारी भारतीय टीम महिला हॉकी विश्व कप 2026 में इकलौता मैच उपविजेता रही मेजबान नीदरलैंड से हारी। हमने ओलंपिक रजत पदक विजेता चीन, इंग्लैंड व ऑस्ट्रेलिया को ड्रॉ पर रोकने के साथ दक्षिण अफ्रीका को 6–1 से और अपने अभियान का समापन मजबूत जर्मनी पर 3–1 की जीत से कर दिखाया कि हमें दुनिया की शीर्ष टीमों को रोकना ही नहीं, उन्हें हराना भी आता है। खासतौर पर आखिरी मैच में जर्मनी जैसी मजबूत टीम पर जीत के बाद जिस तरह हमारी टीम में हरेक के चेहरे पर खुशी थी वह हमारे लिए खासा संतोषजनक और आगे के लिए बेहतर प्रदर्शन का भरोसा देने वाली थी।

भारतीय महिला हॉकी टीम का अगला लक्ष्य क्या है?

बेशक, अब हमारा लक्ष्य जापान में एशियाई खेलों में महिला हॉकी का स्वर्ण पदक जीत सीधे 2028 के लॉस एजेंल्स ओलंपिक खेलों के लिए क्वॉलिफाई करना है। महिला हॉकी विश्व कप में भी हमारा ध्यान अपनी प्रतिद्वंद्वियों, चाहे चीन, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया या फिर जर्मनी हो, उसके बड़े नाम की बजाय अपने खुद के खेल पर रहा। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हमने मैदानी गोल करने के मौकों के साथ पेनल्टी कॉर्नर भी बनाए, लेकिन हम इस अहम मैच में पूरी कोशिश के बाद भी जीत न पाने पर बेहद करीब से सेमीफाइनल से चूक गए। खैर यह सब हमारी टीम की हॉकी यात्रा का एक अहम पड़ाव है।

क्या आपको जापान में ओलंपिक रजत पदक विजेता व एशियाई खेलों के विजेता चीन की दीवार को तोड़ने का भरोसा है?

हम महिला हॉकी विश्व कप में चीन को दो-दो की बराबरी पर रोकने से पहले उससे 1-4 या इसी तरह बड़े अंतर से एशियन चैंपियंस ट्रॉफी और अन्य टूनामेंट में हार रहे थे। अब चीन ही नहीं, दुनिया की कई अन्य शीर्ष टीमों को बराबरी पर रोकने से हममें यह विश्वास आया कि हम किसी भी बड़ी टीम का मुकाबला कर सकते हैं। हमें एशियाई खेलों में चीन से पहले अपने पूल बी में मेजबान जापान से और पूल ए में पिछली उपविजेता दक्षिण कोरिया से पार पाने की बाबत सोचना है। हमें विश्व कप से यह सबक मिला है कि प्रतिद्वंद्वी की बाबत ज्यादा न सोच कर अपने खेल पर फोकस करना है। एशियाई खेलों में हमारी कोशिश हर मैच में, हर क्वॉर्टर और हर मिनट अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने की होगी, क्योंकि किसी भी बड़े मंच पर जरा सी भी ढील भारी पड़ सकती है। हम महिला हॉकी विश्व कप के अपने प्रदर्शन का विश्लेषण करने के बाद यह जानने की कोशिश करेंगे कि हमसे पदक जीतने में कहां क्या चूक हो गई। हम अपनी गलतियों को सुधार कर और जो हमने इसमें अच्छा किया उसे जारी रख इस बार एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे।

2026 के महिला हॉकी विश्व कप में आप जैसी अनुभवी और भारत के लिए अपना पहला विश्व कप खेलने वाली टीम की 11 खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर आपकी राय?

टीम में मुझ जैसी 200 से ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाली करीब आधा दर्जन और कप्तान सलीमा टेटे 100 से ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाली दो खिलाड़ियों के साथ अपना पहला विश्व कप खेलने वाली 11 खिलाड़ियों के बीच बेहतरीन जुगलबंदी

अब हमारा लक्ष्य जापान में एशियाई खेलों में महिला हॉकी का स्वर्ण पदक जीत सीधे 2028 के लॉस एंजेल्स ओलंपिक खेलों के लिए क्वॉलिफाई करना है। महिला हॉकी विश्व कप में भी हमारा ध्यान प्रतिद्वंद्वियों, चाहे चीन, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया या फिर जर्मनी हो, उसके बड़े नाम की बजाय अपने खुद के खेल पर रहा। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हमने मैदानी गोल करने के मौकों के साथ पेनल्टी कॉर्नर भी बनाए, लेकिन हम इस अहम मैच में पूरी कोशिश के बाद भी जीत न पाने पर बेहद करीब से सेमीफाइनल से चूक गए।

का नतीजा है कि हम विश्व कप में पांचवां स्थान हासिल कर पाए। भारतीय टीम में सीनियर खिलाड़ियों की अपनी साथी जूनियर का मार्गदर्शन कर उन्हें परिपक्व बनाने की एक स्वस्थ परंपरा रही है। मैंने, नवजोत, ललरेमसियामी, नेहा, सुशीला चानू और कप्तान सलीमा टेटे ने मौजूदा टीम की जूनियर खिलाड़ियों के साथ लगातार संवाद कर उन्हें सहज करने की कोशिश की, जैसे कि कभी हमारी सीनियर रही रानी रामपाल, वंदना कटारिया और मोनिका जैसी खिलाड़ियों ने हमसे संवाद कर की थी। टीम की नौजवान खिलाड़ियों का जोश मेरे साथ-साथ नेहा, ललरेमसियामी सरीखी सीनियर खिलाड़ियों का अनुभव विश्व कप में बहुत काम आया। टीम की सभी सीनियर खिलाड़ियों ने टीम की नौजवान खिलाड़ियों को खुल कर अपना नैसर्गिक खेल खेलने को प्रोत्साहित किया और इस पर सभी ने अमल भी किया।

आप अपने दशक भर के लंबे अंतर्राष्ट्रीय हॉकी करियर में अलग-अलग उस्तादों के मार्गदर्शन में खेलीं, आपकी राय में कौन सर्वश्रेष्ठ रहा?

मैं जीएस भंगु, सीआर कुमार, नील हागुड, हरेन्द्र सिंह सर, 2017 से 2021 तक शुएर्ड मराइन और अब एक बार फिर बतौर कोच उनके ही मार्गदर्शन में खेल रही हूं। मेरा मानना है कि टीम का कोच कोई भी हो, उसकी पुरजोर कोशिश यही रहती है कि टीम बराबर बढ़िया प्रदर्शन कर जीते। बतौर गोलरक्षक मेरे लिए सभी का आकलन मुश्किल है। मेरी कोशिश हमेशा खुद को अपने हर कोच की रणनीति के मुताबिक ढाल कर अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने की रही और रहेगी।

अब आप अपने अंतर्राष्ट्रीय करियर के ऐसे पड़ाव पर हैं जब आपको कई अहम फैसले लेने पड़ सकते हैं। आप कब तक अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खेलेंगी?

मैंने हॉकी में जो कुछ भी पाया है उसमें मेरी प्रेरणा मेरे दादा जी रंजित सिंह पूनिया रहे हैं। मैं हमेशा दादा जी की तस्वीर अपने साथ रखती हूं। मैं बचपन में बहुत शर्मिली थी। बहुत कम बात करती थी। मेरे दादा जी बेशक पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उन्होंने बराबर मेरी हौसलाअफजाई कर पूरे भरोसे के साथ हॉकी खेलने के लिए हमेशा प्रेरित किया। मेरे हॉकी खेलने पर मेरे बारे में एक बार अखबार में कुछ छपा तो वह मेरे पास उस अखबार में छपी मेरी तस्वीर को लेकर आए और बहुत खुश हुए थे। हॉकी में अपने इतने लंबे सफर के बाद मैं कब तक खेलूंगी इस बाबत मैं आपसे कुछ भी अभी साफ साफ नहीं कह सकती। मुमकिन है कि मैं एशियाई खेलों तक खेलूं, 2028 लास एंजेल्स ओलंपिक तक या फिर आगे, अभी कुछ मैंने तय नहीं किया। मैं खुशकिस्मत हूं मुझे पति और अपनी ससुराल में सभी का साथ मिला। मेरे पति मुझे बराबर हॉकी खेलने को प्रेरित करते हैं। सभी का साफ कहना है कि मैं कब तक हॉकी खेलूंगी, यह फैसला सिर्फ मेरा होगा। फिलहाल तो ध्यान सिर्फ और सिर्फ एशियाई खेलों पर है।■

युवा सहकार हाईलाइट्स

नेशनल युवा कोऑपरेटिव सोसायटी लिमिटेड (एनवाईसीएस) की टीम ने श्री बंशीधर तिवार (आईएएस) को मासिक पत्रिका 'युवा सहकार' भेंट की। श्री तिवारी (बाएं) उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के अतिरिक्त सचिव, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के महानिदेशक और एमडीडीए के उपाध्यक्ष हैं। इस दौरान एनवाईसीएस की टीम को इस कोऑपरेटिव सोसायटी की उन पहलों और विजन को उन्हें बताने का अवसर मिला, जिनका उद्देश्य युवाओं को सशक्त बनाना, सहकारी संस्थाओं को मजबूत करना और सहकारी आंदोलन में युवाओं की अधिक भागीदारी को बढ़ावा देना है।

नेशनल युवा कोऑपरेटिव सोसायटी लिमिटेड की टीम द्वारा एनसीसीएफ और बिस्कोमान के अध्यक्ष श्री विशाल सिंह (दाएं) को मासिक पत्रिका 'युवा सहकार' भेंट की गई। 'युवा सहकार' युवाओं के सशक्तीकरण, सहकारिता के विस्तार और राष्ट्र निर्माण के संकल्प को समर्पित एक महत्वपूर्ण पहल है। यह पत्रिका युवाओं को सहकारिता क्षेत्र की नई संभावनाओं, अवसरों और नवाचारों से जोड़ने का प्रभावी माध्यम बन रही है।

IGL: India's Future Foreword Energy

Leading India's clean energy landscape

IGL believes in a customer-centric approach and provides clean energy solutions through innovative technology and diversification in India and abroad. IGL is playing a crucial role in the emerging scenario, in augmenting its compression capacity by adding new stations and investing in new-age fuels like Liquefied Natural Gas (LNG), Compressed Bio Gas (CBG) and Solar to address changing energy needs.

IGL's core deliverables include:

- IGL is a leading provider of clean and convenient Piped Natural Gas (PNG) and Compressed Natural Gas (CNG).
- IGL offers various services to meet the needs of Residential, Commercial and Industrial customers.
- IGL is a growing company, strongly committed to safety, innovation, and customer satisfaction.

INDRAPRASTHA GAS LIMITED

An ISO 9001, ISO 14001 & OHSMS 45001 Certified Company

CIN No.: L23201DL1998PLC097614

World Trade Centre, Block G, 2nd Floor, Nauroji Nagar, New Delhi-110029, Website: www.iglonline.net

Follow us:

Customer Care

1800 102 5109 / 1800 180 5109 (24x7 Toll Free)